Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-07 01-15 अप्रैल, 2025 (पाक्षिक) ₹20

भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध व क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत हुए

'भाजपा का लक्ष्य एवं ध्येय सत्ता नहीं, सेवा है'

अगरतला (त्रिपुरा) में 09 मार्च, 2025 को प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 18 मार्च, 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

कोकराझार (असम) में 16 मार्च, 2025 को ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 11 मार्च, 2025 को 'उत्तर-पूर्व छात्र एवं युवा संसद' को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 14 मार्च, 2025 को भाजपा कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों के साथ रंगों का त्योहार 'होली' मनाते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य करती है और आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाती है : जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 09 मार्च, 2025 को अगरतला में त्रिपुरा में प्रदेश...

10 **प्रधानमंत्री मोदीजी ने पूर्वोत्तर को भारत सरकार की हर योजना में केन्द्र में रखकर काम किया : अमित शाह**
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह...

11 **दिल्ली की एक प्रमुख सड़क बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से पहचानी जाएगी: अमित शाह**
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 16 मार्च को कोकराझार, असम में...

31 **प्रधानमंत्री ने मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रहण किया**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान मॉरीशस...

32 **भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 6 समझौते और हुईं 4 घोषणाएं**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर...

लेख

तपेदिक से लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर / **जगत प्रकाश नड्डा** 22
नव वर्ष—नव संकल्प / **शिवप्रकाश** 26
अटलजी में एक सच्चा पत्रकार सदैव विद्यमान रहा / **डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी** 28

अन्य

हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत
प्रदेश के 10 में से 9 नगर निगमों पर फराया जीत का परचम 08
मिजोरम में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत 09
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भेंट की 09
4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत की जीडीपी 10 साल में हुई दोगुनी 12
अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान भारत का कुल निर्यात 6.24 प्रतिशत बढ़कर 750.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान 13
देश में कोयला उत्पादन 1 अरब टन के पार हुआ 14
असम में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप IV उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मिली मंजूरी 15
पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. देबेन्द्र प्रधान का निधन 16
कदम सिंह नहीं रहे 16
प्रधानमंत्री ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ ज्ञानवर्धक बातचीत की 17
कमल पुष्प 17
प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा को संबोधित किया 18
केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया 20
पीएम सूर्य घरः भारत की सौर क्रांति 24
भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध व क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत हुए 30
भारत में सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई-बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहां के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहारवासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र-बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। (22 मार्च, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

कांग्रेस की सरकारों के दौरान पोलियो और टिटनेस जैसी दवाओं के आने में बीस या उससे अधिक साल लग गए। वहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड संकट के दौरान 9 माह के अंदर एक नहीं, दो-दो स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई।

(19 मार्च, 2025)

अमित शाह

पहले कश्मीर में चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि चुनकर आते थे, अब वहां जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है। कश्मीर में पहली बार लोकतंत्र की नींव मोदी जी ने डाली है।

(21 मार्च, 2025)

राजनाथ सिंह

नासा के क्रू-9 की धरती पर सुरक्षित वापसी पर बधाई! भारत की बेटी सुनीता विलियम्स एवं क्रू-9 के अन्य यात्रियों ने अंतरिक्ष में मानवीय सहनशीलता और दृढ़ता का इतिहास पुनः लिखा है। सुनीता विलियम्स की यह अविश्वसनीय यात्रा, अटूट समर्पण, दृढ़ता एवं लड़ने की भावना दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उनकी सुरक्षित वापसी पूरी दुनिया के लिए जश्न मनाने का क्षण है। उनका साहस और उपलब्धियां हम सभी को गौरवान्वित करती रहेंगी। उन्हें धरती पर सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी हितधारकों को बधाई एवं बहुत-बहुत धन्यवाद। (19 मार्च, 2025)

बी.एल. संतोष

भाजपा ने चकमा स्वायत्त जिला परिषद् में संपन्न ग्राम परिषद् चुनावों में भव्य जीत हासिल की है। 88 वीसी में से भाजपा मिजोरम को 64 वीसी पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को केवल नैतिक जीत हासिल हुई और सत्तारूढ़ जेडपीएम 12 वीसी पर सीमित रही। पार्टी ने 516 सीटों में से 364 सीटें जीती है। भाजपा मिजोरम टीम को बधाई! (13 मार्च, 2025)

मनोहर लाल

100 स्मार्ट शहरों में झुग्गियों की जगह मकान बनाने के क्रम में अब तक 5,52,000 घर स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 4,99,000 मकान निर्माणाधीन हैं और 3,36,000 मकान बनकर तैयार हो गए हैं तथा वर्ष के अंत तक बाकी बचे हुए मकानों का भी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

(17 मार्च, 2025)

संपादकीय

जीडीपी के दोगुने होने से 'विकसित भारत' के विजन को मिला बल

आज जब वर्ष 2025 के आरंभ में ही भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.3 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, पिछले दस वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के चमत्कारिक परिवर्तन पर पूरा विश्व अचंभित हो रहा है। भारत, जिसकी जीडीपी में पिछले दस वर्षों में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है, आज विश्व की न केवल सबसे तेज विकास दर वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि इस दशक में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली जीडीपी भी बन गई है। देश की जीडीपी जो 2013-2014 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, आज 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। यह 105 प्रतिशत की वृद्धि है जो विश्व की अर्थव्यवस्था में किसी अन्य देश ने प्राप्त नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे कांग्रेसनीत यूपीए के दौर में 'फ्रेजाइल फाइव' के अंतर्गत गिना जाता था, आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विश्व के 'टॉप फाइव अर्थव्यवस्था में शामिल है। इतना ही नहीं, आज भारत विश्व का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है।

जहां अर्थव्यवस्था में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 2014 से 2024 के मध्य 709.84 बिलियन डॉलर का सीधा निवेश हुआ है। यह कांग्रेसनीत यूपीए के दौर (2004-2014) के दौरान हुए 320 बिलियन डॉलर से 119 प्रतिशत अधिक है। मोदी सरकार के काल में भारत के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है जो कांग्रेसनीत यूपीए के दौर के 466 बिलियन डॉलर (2013-2014) से बढ़कर 2023-24 में 778 बिलियन डॉलर हो गई। यह 67 प्रतिशत की वृद्धि है। साथ ही, देश का निर्यात 2020-21 में जीडीपी के 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में जीडीपी का 21.85 प्रतिशत हो गया जो कि कोविड-19 महामारी के पश्चात् अर्थव्यवस्था के पुनः सुदृढ़ीकरण को परिलक्षित करता है। सेवा निर्यात भी 2014-2024 के दौरान दुगुना से भी अधिक होकर 709.84 बिलियन डॉलर हो गया जो कांग्रेस-नीत यूपीए के दौर में केवल 305 बिलियन डॉलर था। यह वृद्धि 'मेक इन इंडिया', पीएलआई जैसे योजनाओं के कारण हुआ है जिसने देश की उत्पादन क्षमता तथा वैश्विक स्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोविड-19 महामारी तथा रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आज 2025 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत अनुमानित है जो कि विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। व्यक्तिगत स्तर पर विकास की द्योतक प्रति व्यक्ति आय भी 2014 के 86,647 रुपए से बढ़कर 2024 में 2.12 लाख रुपए हो चुका है, जो देश के बढ़ते जीवन-स्तर को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसका एक व्यापक परिणाम यह है कि 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा अति गरीबी भी 1 प्रतिशत से नीचे आ चुकी है। यह चहुंमुखी परिवर्तन एनडीए शासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भारी सुधार के कारण संभव हुआ है।

> **मोदी सरकार की अद्भुत आर्थिक उपलब्धियों से सुशासन, वित्तीय अनुशासन एवं अवसंरचना-नीत विकास के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता रेखांकित होती है। देश की जीडीपी दोगुनी से भी अधिक होने से अब यह निश्चित लगता है कि आने वाले दो-तीन वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा**

मोदी सरकार की जन-धन योजना के कारण वित्तीय समावेश में व्यापक वृद्धि हुई तथा 53 करोड़ जन-धन बैंक खातों के माध्यम से देश के जन-जन के लिए अभूतपूर्व रूप से बैंकों के दरवाजे खुल गए हैं। जैम त्रिमूर्ति (जन-धन-आधार-मोबाइल) के माध्यम से डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) संभव हुआ है जिसका उदाहरण कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आया जब 27,442 करोड़ रुपए 11.42 करोड़ लाभार्थियों को 24 दिनों के अंदर आसानी से हस्तांतरण संभव हुआ। साथ ही, 2012-13 के 2.2 बिलियन डिजिटल लेन-देन के स्थान पर 2024 में 208.5 बिलियन डिजिटल लेन-देन अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते कदम के उदाहरण हैं।

मोदी सरकार की अद्भुत आर्थिक उपलब्धियों से सुशासन, वित्तीय अनुशासन एवं अवसंरचना-नीत विकास के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता रेखांकित होती है। देश की जीडीपी दोगुनी से भी अधिक होने से अब यह निश्चित लगता है कि आने वाले दो-तीन वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरना 'विकसित भारत' के पथ को प्रशस्त कर रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

त्रिपुरा भाजपा सरकार की द्वितीय वर्षगांठ पर आयोजित जनसभा

भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य करती है और आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाती है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 09 मार्च, 2025 को अगरतला में त्रिपुरा में प्रदेश सरकार की द्वितीय वर्षगांठ पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा को सरकार के दो वर्ष पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही, उन्होंने जनता को भाजपा सरकार से पूर्व लेफ्ट की सरकार में त्रिपुरा के अराजक दौर को भी याद कराया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं बालिका समृद्धि योजना व मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मंच पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, राज्यसभा सांसद श्री राजीब भट्टाचार्य, लोकसभा सांसद डॉ. संबित पात्रा, सांसद श्रीमती कृति देवी देबबर्मन, पूर्व सांसद श्री राजदीप राय सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य सरकार में मंत्री एवं वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।

भाजपा का ध्येय सत्ता नहीं, सेवा

श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा को दो वर्ष पूर्ण करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्रिपुरा की जनता ने 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दो की दो सीटें देकर आशीर्वाद दिया है। त्रिपुरा की जनता कमल के निशान को और प्रधानमंत्रीजी को बारंबार आशीर्वाद इसलिए दे रही है, क्योंकि भाजपा जनता की सेवक है, जनता की चिंता करती है और जनता की सेवा के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य करती है और आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और ध्येय सत्ता नहीं, सेवा है। भाजपा सत्ता का उपयोग सेवा के लिए करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सत्ता में लगातार तीसरी बार विराजमान रहकर प्रधानसेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। एक समय था जब पत्रकार 'एंटी इन्कमबेंसी' की बात करते थे यानी जनता सरकार से असंतुष्ट है, नाखुश है और नहीं चाहती है कि सरकार दोबारा आए, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद राजनीति की संस्कृति में बदलाव आया है और आज भारत व त्रिपुरा की जनता 'एंटी इन्कमबेंसी' नहीं बल्कि 'प्रो इन्कमबेंसी' की बात करती है। 'प्रो इन्कमबेंसी' का मतलब है कि जनता सरकार से संतुष्ट है और मोदीजी व साहाजी की सरकार को वापस लेकर आना चाहती है। त्रिपुरा की भाजपा सरकार, गांव, गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा, किसान, वंचित, शोषित और समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है।

त्रिपुरा सरकार की उपलब्धियां

श्री नड्डा ने त्रिपुरा की जनता से अपना आशीर्वाद देने की अपील करते हुए कहा कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोग्राम के 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इससे 1 लाख 46 हजार हेक्टेयर भूमि को फायदा हुआ। भाजपा सरकार ने 53.900 मीट्रिक टन चावल एमएसपी पर खरीद कर 27,800 किसानों को लाभ दिया है। भाजपा सरकार ने 6,57,00 किसान क्रेडिट वितरित किए और इनके माध्यम से 570 रुपए की राशि किसानों की मुहैया कराई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है और 19,000 किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, हॉर्टिकल्चर और बागवानी में मुख्यमंत्री स्वनिर्भर योजना में 96000 लोगों ने भाग लिया है, अर्बन हॉर्टीकल्चर में 9575 घरों ने प्लांट वितरण से लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री प्राणी संपदा विकास योजना के तहत 11 करोड़ रुपए दिए गए और 66600 मछुआरों को मत्स्य पालन के वैज्ञानिक तरीके सिखाए गए।

उन्होंने कहा त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने 4500 स्कूलों को नवाचार से जोड़ा और 137 स्मार्ट क्लासरूम बनाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत 7 लाख 77 हजार परिवारों और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 4 लाख 30 हजार लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया है। त्रिपुरा में सड़कों, रेलवे, एयरवे में सुधार हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है और आज इन्फ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा आज नए आयाम तय कर रहा है। त्रिपुरा में 462 किमी की सड़क बनी है और 2024-25 में ही 180 किमी सड़क बनी है। सामाजिक कल्याण योजनाओं में 3 लाख 77 हजार महिलाओं को 2000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। 33 हजार आदिवासी छात्रों के विकास के लिए 68 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई है। वंदन केन्द्र में 27 आदिवासी समुदायों को लाभ मिला है। लेफ्ट (सीपीआईएम) के राज में रक्तरंजित रहे त्रिपुरा में आज भाजपा के कार्यकाल में अपराध दर में 20 प्रतिशत की गिरावट आ गई है और त्रिपुरा आज भारत में तीसरा सबसे कम अपराध दर वाला राज्य है। नशे के खिलाफ लड़ाई में अब तक 64 हजार किलो गांजा जब्त किया गया है और त्रिपुरा को नशामुक्त त्रिपुरा बनाने की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। आज त्रिपुरा का सचिवालय पूरी तरह डिजिटलाइज्ड हो गया है और 29 लाख फाइल्स डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड हो गया है। त्रिपुरा में फुटबॉल का सिंथेटिक ग्राउंड बना है, खेलो त्रिपुरा के तहत त्रिपुरा में अभी अभी पैरा गैम्स हुए और इसी तरह भाजपा त्रिपुरा को मुख्यधारा में लेकर आ रही है। त्रिपुरा में विकास का पत्थर सिर्फ या तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी या वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में लगा है। अटलजी के प्रधानमंत्री बनने पर पूर्वोत्तर मंत्रालय बना और मोदीजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत सरकार के मंत्री पूर्वोत्तर आने लगे। भारत मंडपम में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा को यूपीए सरकार में मिलने वाले टैक्स डिवोल्यूशन में पांच गुना इजाफा किया है। 2014 में त्रिपुरा को मात्र 9 हजार करोड़ रुपए मिलते थे और आज त्रिपुरा को भाजपा कार्यकाल में 46 हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ग्रांटेड एड 73 प्रतिशत के इजाफे के साथ 31 हजार करोड़ से बढ़कर 54 हजार करोड़ रुपए हो गई है।

उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2016 में त्रिपुरा को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन मिल गई और आज त्रिपुरा 23 एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से मुख्यधारा से जुड़ गया है। अगरतला, उदयपुर, कुमारनगर और धर्मपुर रेलवे स्टेशन दो वर्ष के अंदर अमृत भारत के तहत विकसित किए जाएंगे। तीन नए रूट संचालित किए गए हैं और अगरतला को कृषि उड़ान योजना से जोड़ दिया गया है, महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट का भी नवीनीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज पूरे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और त्रिपुरा में 24 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत त्रिपुरा के 4 लाख 70 मकान सहित पूरे देश में 4 करोड़ मकान बनाए गए हैं, किसान सम्मान निधि से त्रिपुरा के 2 लाख 60 किसान सहित पूरे देश के 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं और स्वच्छ भारत मिशन में 4 लाख 50 हजार इज्जतघर त्रिपुरा में बनाने के साथ पूरे देश में 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं।

दो नई योजनाओं की घोषणा

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट की घालमेल की सरकार थी। अंदर से दोस्ती थी और ऊपर से नूरा कुश्ती थी। सत्ता के भूखे लोगों ने त्रिपुरा को खून से सनी जमीन बना दिया था, आए दिन बलात्कार और हत्याएं हो रही थीं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एक, ऑटोड्राइवर कार्यकर्ता की कांग्रेस के समर्थन में सीपीआईएम के लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी लेकिन आज भाजपा सरकार में त्रिपुरा में माताएं-बहनें सुरक्षित कहीं भी आ-जा सकती हैं, कोई भी उन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब विकास की बात करती है तो जनता को कम्युनिस्ट पार्टी का लाल आतंक भी याद रखना चाहिए, उनका भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी भी याद रखनी चाहिए। त्रिपुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर कमल खिलाने में सहयोग करती रहे, तो इसी तरह त्रिपुरा का विकास होता रहेगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दो नई योजनाओं की घोषणा की। पहली मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, जिसके तहत त्रिपुरा के हर बीपीएल परिवार में बिटिया के जन्म पर उसके नाम पर सरकार 50 हजार रुपये का बॉन्ड भरेगी और जब बिटिया 18 वर्ष की होगी तो उसे वो बॉन्ड मिल जाएगा, तब उसकी कीमत 10 लाख रुपये होगी। दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है जिसके तरह त्रिपुरा एजुकेशन बोर्ड, सीबीएससी और आईएससी बोर्ड के बच्चों को मिलाकर सबसे अधिक अंक लाने वाली 140 बेटियों को हमारी राज्य सरकार स्कूटी देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव महिलाओं और बच्चियों को प्रोत्साहित किया है, इसी तर्ज पर त्रिपुरा सरकार भी इन योजनाओं को लेकर आई है। ■

हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत

प्रदेश के 10 में से 9 नगर निगमों पर फहराया जीत का परचम

हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने के पांच महीने बाद भाजपा ने 12 मार्च, 2025 को जारी परिणामों के अनुसार प्रदेश के 10 नगर निगमों में से नौ नगर निगमों पर विजय प्राप्त की। वहीं, केवल मानेसर में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की।

विधानसभा चुनावों के अपने निराशाजनक प्रदर्शन को जारी रखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक बार पुनः विफलता ही हाथ लगी।

गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत एवं यमुनानगर में भाजपा उम्मीदवारों ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वियों को हराकर भव्य जीत दर्ज की। नौ नगर निगमों के लिए मतदान 02 मार्च, 2025 को हुआ था, जबकि पानीपत के लिए मतदान 9 मार्च, 2025 को हुआ था।

हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा भाजपा को शानदार जीत के लिए बधाई देते हुए कहा, "हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार। यह जीत राज्य में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता-जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इस महाविजय में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बड़ी भूमिका रही है, जिसके लिए मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं।"

हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा नगर निगम चुनाव में भाजपा को मिली शानदार विजय को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के विकास और जनकल्याण कार्यों पर हरियाणा की जनता की मुहर बताया। श्री नड्डा ने इस ऐतिहासिक विजय के लिए हरियाणा की जनता का धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडौली सहित प्रदेश के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी।

श्री नड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर विश्वास जताया है। हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, जो रफ्तार के साथ नॉन-स्टॉप हरियाणा के कार्य को पूर्ण करेगी। हरियाणा में कांग्रेस की खस्ता हालत से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी पर अब जनता को बिल्कुल विश्वास नहीं है। यह ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में क्रियान्वित हो रही समावेशी, विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी नीतियों पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास का प्रतीक है।

श्री नड्डा ने आगे कहा कि यह जीत हरियाणा की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का संकल्प है और यह दर्शाती है कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, जैसे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और युवाओं के लिए रोजगार अवसर, को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और विकास के नए आयाम गढ़ेगा। ■

मिजोरम में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत

भारतीय जनता पार्टी ने 12 मार्च, 2025 को घोषित परिणामों के अनुसार मिजोरम में चकमा स्वायत्त जिला परिषद् (सीएडीसी) के लिए हुए चुनावों में 88 ग्राम परिषद् सीटों में से 64 सीटों पर शानदार विजय प्राप्त की। 88 सीटों में से 12 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार विजयी घोषित हुए, जिनमें से 9 सीटें भाजपा ने जीतीं और शेष तीन सीटें ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने जीतीं।

कांग्रेस इन चुनावों में एक भी परिषद् सीट जीतने में विफल रही। यह हार चकमा स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की पहली बड़ी हार है। सत्तारूढ़ जेडपीएम 12 सीटें हासिल करने में सफल रही, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने 8 सीटें जीतीं।

उल्लेखनीय है कि 2020 के स्थानीय चुनाव में एमएनएफ, जो कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी थी, ने 64 ग्राम परिषद् सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी।

मिजोरम की जनता का आभार: जगत प्रकाश नड्डा

मिजोरम के लोगों को बधाई देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'एक्स' पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "चकमा स्वायत्त जिला परिषद् (सीएडीसी) में ग्राम परिषद् चुनाव 2025 में भाजपा को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मिजोरम के लोगों का आभार। यह प्रचंड जनादेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण एवं विकास यात्रा में लोगों के भरोसे का प्रमाण है। मैं भाजपा, मिजोरम के कार्यकर्ताओं को इस जीत को हासिल करने में उनके अथक समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता हूं और उनकी सराहना करता हूं।" ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भेंट की

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'भाजपा को जानें' पहल के तहत 18 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन से भेंट की।

इस भेंट में श्री नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, सदस्यता अभियान, रणनीतियों और वर्तमान में चल रही जन कल्याणकारी पहलों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने 'भाजपा को जानें' पहल पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री नड्डा ने भाजपा एवं न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के बीच आदान-प्रदान पर भी बात की, जिसका उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और संगठनात्मक दृष्टिकोण को लेकर अधिक जानकारी प्राप्त करना है।

इस बातचीत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की प्रगति, विशेष रूप से प्रसवपूर्व एवं नवजात देखभाल, संस्थागत प्रसव एवं बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा में प्रगति पर भी चर्चा की गई। श्री नड्डा ने सुझाव दिया कि भारत अपनी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं एवं किफायती उपचार के साथ चिकित्सा पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को न्यूजीलैंड भेजने से ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे दोनों देशों के चिकित्सा क्षेत्रों को लाभ होगा।

इस भेंट के दौरान श्री नड्डा के साथ भाजपा विदेश विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आये थे। यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी ने पूर्वोत्तर को भारत सरकार की हर योजना में केन्द्र में रखकर काम किया : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 11 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन (Student Experience in Inter-State Living) द्वारा आयोजित 'उत्तर-पूर्व छात्र एवं युवा संसद (North-East Students' & Youth Parliament)' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरे हुए हमारे उत्तर-पूर्व का आज़ादी से पहले भारत की जीडीपी में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान था, जो आज घटकर 7 प्रतिशत से नीचे आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट में पूरी दुनिया को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में भारत के सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले युवा हैं और सबसे मेहनती जनजातियां यहीं हैं। श्री शाह ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य गहना है और ये क्षेत्र भारत की संस्कृति को अति समृद्ध करने वाली विरासतों से लैस है। उन्होंने कहा कि यहां 220 से अधिक जनजातीय समूह हैं, 160 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, 200 से अधिक बोलियां और भाषाएं हैं, 50 यूनिक प्रकार के त्योहार हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध 30 से अधिक नृत्य शैलियां हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में 78 से अधिक यूनिक वाद्य यंत्र हैं और 100 से अधिक अलग-अलग परिधान हैं।

पूर्वोत्तर को प्राथमिकता

श्री शाह ने कहा कि जब भी हमारी पार्टी की सरकार आई हमने पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पहले इतने बड़े और पिछड़े भूभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था, लेकिन अटलजी की सरकार में इसकी स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर को भारत सरकार की हर योजना में केन्द्र में रखकर काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नॉर्थ-ईस्ट और भारत के बाकी भागों के बीच की दूरी को कम कर दिया। श्री शाह ने कहा कि उत्तर-पूर्व के हर राज्य की राजधानी 2027 तक रेल, हवाई मार्ग और सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदीजी ने न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाकर उत्तर-पूर्व को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ा, बल्कि फिज़िकल दूरी के साथ-साथ दिलों की दूरियां मिटाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर योजना के केन्द्र में पूर्वोत्तर को रखकर और एक के बाद एक वहां के हर उग्रवादी समूह से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुन, समझ और उनके साथ समझौते कर उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 10 साल में उत्तर-पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच नॉर्थ-ईस्ट में 11 हज़ार हिंसा की घटनाएं हुईं जबकि 2014 से 2024 के बीच सगभग 70 प्रतिशत की कमी के साथ ये संख्या 3428 रह गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों की मृत्यु में 70 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सभी उग्रवादी समूहों के साथ मोदी सरकार ने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज़्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेनस्ट्रीम में आए हैं। श्री शाह ने कहा कि 10 साल में हमने विद्रोही समूहों के साथ 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के तहत उत्तर-पूर्व की भाषाओं, बोलियों, संस्कृति, वेशभूषा, परंपरागत नृत्य और कलाओं को सम्मानित किया, संरक्षित किया और 10 हज़ार लोगों से हथियार डलवाकर पूरे उत्तर-पूर्व में शांति का माहौल खड़ा किया।

पूर्वोत्तर का विकास

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई प्रयास किए गए और बजटरी प्रोविज़न को भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 की तुलना में 2024-25 के बजट में 153 प्रतिशत की वृद्धि करने का काम नरेन्द्र मोदीजी ने किया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 41 हजार करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च किए, 47 हजार करोड़ रुपए अलग से ग्रामीण सड़कों पर खर्च किए। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से 90 हजार करोड़ रुपए नॉर्थ-ईस्ट में सिर्फ सड़कों के लिए मोदी सरकार ने खर्च किए। श्री शाह ने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के लिए 64 नए रूट शुरू किए, वायब्रेंट विलेज कार्यक्रम में 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जो विशेषकर अरुणाचल को फायदा पहुंचाता है और रेलवे के लिए 18 हज़ार करोड़ रुपए दिए।

श्री शाह ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार के दिल के बहुत नजदीक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट आवंटन नहीं बल्कि नॉर्थ-ईस्ट का विकास, एकता और शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। ■

दिल्ली की एक प्रमुख सड़क बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से पहचानी जाएगी: अमित शाह

मोदी सरकार अगले दो वर्षों में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) शांति समझौते को शत-प्रतिशत क्रियान्वित करेगी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 16 मार्च को कोकराझार, असम में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) के 57वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि आज बोडोलैंड क्षेत्र में कायम शांति, विकास और उत्साह में एबीएसयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। एबीएसयू की भूमिका के बगैर बोडो समझौता नहीं हो पाता और बोडोलैंड में शांति स्थापित नहीं हो पाती।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज जब पूरा बोडोलैंड अपने नेता बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा के बताए रास्ते पर चल रहा है, ऐसे समय में केन्द्र सरकार ने दिल्ली में एक प्रमुख सड़क का नामकरण बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि 27 जनवरी, 2020 को जब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो विपक्ष मजाक उड़ा रहा था, लेकिन आज केन्द्र सरकार और असम सरकार ने इस समझौते की 82 प्रतिशत शर्तों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अगले दो वर्षों में इस समझौते को शत-प्रतिशत क्रियान्वित कर देगी। इसके बाद बीटीआर में चिरकालिक शांति होगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीटीआर शांति समझौते के तहत सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 को पूरे बीटीआर क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) हटा लिया। श्री शाह ने कहा कि बोडोलैंड के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि इस क्षेत्र की आबादी मात्र 35 लाख है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

श्री अमित शाह ने कहा कि सैकड़ों युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाया गया है। कई सारे हथियार सरेन्डर हुए हैं और पिछले तीन साल में असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड के 4,881 सदस्यों के पुनर्वास पर 287 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इसका 90 प्रतिशत हिस्सा मोदी सरकार ने दिया है। श्री शाह ने कहा कि रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री श्री हेमन्ता बिस्वा सरमा ने 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती करके एक नई शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने असम में कुल नौ उग्रवादी संगठनों से समझौते करके 10,000 से ज्यादा युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर को उग्रवाद, आंदोलन, ब्लॉकेड, बंद और हिंसा जैसी समस्याओं से मुक्त कराकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी और हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में हाल में इनवेस्टमेंट समिट हुई, जिससे पांच लाख करोड़ रुपए का निवेश असम में आ रहा है। ■

राजीव चंद्रशेखर केरल प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष चुने गए

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजीव चंद्रशेखर को 24 मार्च, 2025 को केरल भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। अपना कार्यभार संभालने के बाद श्री चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह अपने प्रदेश की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है... हम जानते हैं कि हमें केरल में बदलाव लाना है। हम यह भी जानते हैं कि केरल के लोगों के जीवन में, केरल की अर्थव्यवस्था में, निवेश लाने के लिए, युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए हमें सरकार में रहना होगा और इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम राज्य को एक विकल्प प्रदान करने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयास करें, जिसे पिछले 70 वर्षों में दो मोर्चों ने तबाह कर दिया है। केरल आज नीचे की ओर जा रहा है और हम चाहते हैं कि केरल 'विकसित केरल' बने...।" ■

4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत की जीडीपी 10 साल में हुई दोगुनी

105 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह दुनिया की सबसे तीव्र वृद्धि है तथा भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुनी से भी अधिक बढ़ाकर जी-7, जी-20 और ब्रिक्स के सभी देशों को पीछे छोड़ा

भारत पिछले दस वर्षों के दौरान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में इसकी वृद्धि 105 प्रतिशत रही है।

आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से भारत ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2015 में यह 2.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी और तब से भारत ने सकल घरेलू उत्पाद के मामले में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना से भी अधिक कर लिया है।

भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर

भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। जापान की जीडीपी वर्तमान में 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत 2025 की तीसरी तिमाही तक उस आंकड़े को पार कर सकता है। अगर विकास की औसत दर इसी तरह जारी रही तो भारत 2027 की दूसरी तिमाही तक जर्मनी - जो वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है - को पीछे छोड़ देगा। जर्मनी की जीडीपी वर्तमान में 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुनी से भी अधिक बढ़ाकर जी-7, जी-20 और ब्रिक्स के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है।

विकास की गति के मामले में भारत शीर्ष पर रहा, जबकि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में शीर्ष दो स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका (30.3 ट्रिलियन डॉलर) और चीन (19.5 ट्रिलियन डॉलर) रहे। जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है, जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है और भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है।

भारत की विकास यात्रा

भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद को ट्रिलियन डॉलर के निशान (2007 में) तक पहुंचने में 60 साल लगे। 1 ट्रिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 7 साल लगे (2014 में) और कोविड-19 के बावजूद भारत 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर के निशान तक पहुंच गया। 3 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर तक की यात्रा में सिर्फ 4 साल लगे।

इस गति से अगर प्रगति जारी रही, तो भारत हर 1.5 साल में अपने सकल घरेलू उत्पाद में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ने में सक्षम होगा और संभवतः 2032 के अंत तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। ■

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान भारत का कुल निर्यात 6.24 प्रतिशत बढ़कर 750.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 मार्च को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान भारत का कुल निर्यात 750.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 6.24 प्रतिशत की सकारात्मक बढ़ोतरी दर्शाता है। अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान कुल आयात 839.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 7.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान माल निर्यात का कुल मूल्य 395.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-फरवरी 2024-25 में कुल गैर-पेट्रोलियम निर्यात 337.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-फरवरी 2023-24 में 316.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में इसमें 6.43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान माल आयात 656.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान यह 621.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

फरवरी, 2025 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं मिलाकर) 71.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो फरवरी, 2024 के मुकाबले 3.16 प्रतिशत की सकारात्मक बढ़ोतरी दर्शाता है। फरवरी, 2025 में कुल आयात (माल और सेवाएं मिलाकर) 67.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो फरवरी, 2024 के मुकाबले (-)11.34 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

फरवरी, 2025 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 28.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि फरवरी, 2024 में यह 29.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। फरवरी, 2025 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न एवं आभूषणों (सोना, चांदी और कीमती धातु) का आयात 35.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि फरवरी, 2024 में यह 33.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

फरवरी, 2025 में व्यापारिक निर्यात में बढ़ोतरी के प्रमुख चालकों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चावल, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिजों सहित खनिज, सभी टेक्सटाइल्स और कॉफी के आरएमजी शामिल हैं। ■

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप का शुभारंभ

बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 17 मार्च को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप शुरू किया। उल्लेखनीय है कि बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस योजना) का लक्ष्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पायलट प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 03.10.2024 को लॉन्च किया गया था।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रोजगार, कौशल और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पांच योजनाओं का पैकेज पेश करने में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम इंटर्नशिप योजना में कक्षा में सीखने और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने उद्योग से इस योजना में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी देश में कुशल कार्यबल को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देगी। ■

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन का 70 प्रतिशत से अधिक यूपीआई आधारित

'रुपे डेबिट कार्ड और व्यक्ति से व्यापारी के बीच (पी2एम) कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने से संबंधित प्रोत्साहन योजना' ने देश में डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कुल डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8,839 करोड़ से 46 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गए हैं। यह वृद्धि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) द्वारा संचालित है, जोकि 69 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बढ़ी है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,597 करोड़ लेनदेन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ लेनदेन हो गई है।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी 11 मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में यूपीआई का योगदान करीब 70 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे (यानी क्यूआर कोड और पीओएस टर्मिनल), नए व्यापारियों को शामिल करने और थर्ड पार्टी ऐप प्रदाताओं (टीपीएपी) में भी इस योजना अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। ■

देश में कोयला उत्पादन 1 अरब टन के पार हुआ

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 55 प्रतिशत के लिए कोयले पर निर्भर है और देश की लगभग 74 प्रतिशत बिजली कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है

भारत ने कोयला उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 20 मार्च, 2025 को एक अरब टन (बीटी) को पार कर गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 997.83 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन से 11 दिन पहले प्राप्त की गई है, जो भारत की अपनी ऊर्जा मांगों को सुनिश्चित करने और औद्योगिक, कृषि और समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करती है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 55 प्रतिशत के लिए कोयले पर निर्भर है और देश की लगभग 74 प्रतिशत बिजली कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है।

रिकॉर्ड कोयला उत्पादन सरकार के रणनीतिक सुधारों और नीतियों को दर्शाता है, जैसेकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन और कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी के माध्यम से कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। इन पहलों से घरेलू कोयले की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे आयात में उत्तरोत्तर कमी आई है और विदेशी मुद्रा बचत में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

सरकार की उपलब्धियां

अप्रैल से दिसंबर 2024 तक भारत के कोयला आयात में 8.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 5.43 अरब डॉलर (42,315.7 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

देश के लिए गौरव का क्षण: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 मार्च को देश की एक अरब टन कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति देश की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे 'देश के लिए गौरव का क्षण' बताया तथा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के पूर्ण समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने एक्स पोस्ट में बताया कि देश ने एक अरब टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "भारत के लिए गर्व का क्षण! एक अरब टन कोयला उत्पादन को पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह उपलब्धि इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के समर्पण और कड़ी मेहनत को भी दर्शाती है।" ■

कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को दी मंजूरी

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम से 18 लाख 74 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं; 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को मंजूरी दे दी। संशोधित एनपीडीडी केंद्रीय योजना है, जिसमें 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल 2790 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा।

संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण द्वारा डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य किसानों को बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना, मूल्य संवर्धन द्वारा बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और आपूर्ति शृंखला दक्षता बढ़ाना है। इससे पशु पालक किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण विकास में वृद्धि होगी।

एनपीडीडी के क्रियान्वयन से व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इससे 18 लाख 74 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं; 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। इससे प्रतिदिन 100 लाख 95 हज़ार लीटर दूध खरीद क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

एनपीडीडी बेहतर दूध परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने में भी सहायक रहा है। इसके 51,777 से अधिक ग्राम-स्तरीय दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है और 123 लाख 33 हज़ार लीटर की संयुक्त क्षमता वाले 5,123 बल्क दुग्ध शीतक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 169 प्रयोगशालाओं को फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड (एफटीआईआर) मिल्क एनालाइजर के साथ समुन्नत बनाया गया है और 232 डेयरी संयंत्रों में मिलावट का पता लगाने के लिए उन्नत व्यवस्था स्थापित की गई है। ■

वर्ष 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1663.91 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1645.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान

चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन का रिकार्ड उत्पादन

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों (केवल खरीफ एवं रबी) के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 10 मार्च को जारी कर दिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य कृषि फसलों के आंकड़ों को मंजूरी देते और जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और कृषि मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कृषि फसलों का उत्पादन भी रिकार्ड स्तर पर बढ़ रहा है।

विभिन्न फसलों (खरीफ एवं रबी) के उत्पादन का विवरण निम्न है:

- **खरीफ खाद्यान्न– 1663.91 लाख मीट्रिक टन; रबी खाद्यान्न (ज़ायद मौसम शामिल नहीं)– 1645.27 लाख मीट्रिक टन**
- **खरीफ चावल– 1206.79 लाख मीट्रिक टन (रिकार्ड); रबी चावल (ज़ायद मौसम शामिल नहीं)– 157.58 लाख मीट्रिक टन**
- **गेहूं– 1154.30 लाख मीट्रिक टन (रिकार्ड)**
- खरीफ मक्का– 248.11 लाख मीट्रिक टन (रिकार्ड); रबी मक्का (ज़ायद मौसम शामिल नहीं)– 124.38 लाख मीट्रिक टन
- खरीफ श्री अन्न– 137.52 लाख मीट्रिक टन; रबी श्री अन्न (ज़ायद मौसम शामिल नहीं)– 30.81 लाख मीट्रिक टन
- तूर– 35.11 लाख मीट्रिक टन; चना– 115.35 लाख मीट्रिक टन; मसूर– 18.17 लाख मीट्रिक टन
- खरीफ तिलहन– 276.38 लाख मीट्रिक टन; रबी तिलहन (ज़ायद मौसम शामिल नहीं)– 140.31 लाख मीट्रिक टन
- खरीफ मूंगफली– 104.26 लाख मीट्रिक टन (रिकार्ड); रबी मूंगफली (ज़ायद मौसम शामिल नहीं)– 8.87 लाख मीट्रिक टन
- सोयाबीन– 151.32 लाख मीट्रिक टन (रिकार्ड); रेपसीड और सरसों– 128.73 लाख मीट्रिक टन
- गन्ना– 4350.79 लाख मीट्रिक टन
- कपास– 294.25 लाख गांठें (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)
- जूट– 83.08 लाख गांठें (प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम) ■

असम में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप IV उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मिली मंजूरी

इस परियोजना से देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा

सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसकी अनुमानित कुल परियोजना लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है तथा ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 है। यह नई निवेश नीति, 2012 (7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधनों सहित) के तहत एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। नामरूप-IV परियोजना के चालू होने की संभावित समय-सीमा 48 महीने है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों में निर्धारित सीमाओं में छूट देते हुए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल) की 18 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी को भी मंजूरी दी।

प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में इक्विटी पैटर्न निम्नानुसार होगा:

i) असम सरकारः 40%
ii) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल): 11%
iii) हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल): 13%
iv) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): 18%
v) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल): 18%

बीवीएफसीएल की इक्विटी हिस्सेदारी मूर्त परिसंपत्तियों के बदले में होगी।

इस परियोजना से देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। नामरूप-IV इकाई की स्थापना अधिक ऊर्जा कुशल होगी। इससे क्षेत्र के लोगों के लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इससे देश में यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ■

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. देबेन्द्र प्रधान का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. देबेंद्र प्रधान का 17 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में निधन हो गया। डॉ. प्रधान 84 वर्ष के थे। 16 जुलाई, 1941 को जन्मे डॉ. प्रधान ने 1966 में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अपना करियर एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन सामाजिक सेवा के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ओडिशा में भाजपा संगठन को स्थापित करने में डॉ. प्रधान की प्रमुख भूमिका रही, वह 1983 में भाजपा से जुड़े।

डॉ. प्रधान ने 1984 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। वह 1988 से 1993 तक लगातार दो बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल 1995 से 1997 तक रहा।

डॉ. प्रधान 1998 में देवगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। उसी वर्ष वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भूतल परिवहन मंत्री बने। उन्होंने 1999 में फिर से देवगढ़ से चुनाव जीता और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन और कृषि मंत्री बने। डॉ. प्रधान 2001-02 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में उनके पुत्र एवं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जाकर डॉ. प्रधान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के मुख्यमंत्रियों, पार्टी नेताओं, विपक्ष के नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एवं हजारों कार्यकर्ताओं ने भी नई दिल्ली तथा भुवनेश्वर में डॉ. प्रधान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। 18 मार्च, 2025 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गद्वार (पुरी), ओडिशा में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

एक मेहनती और विनम्र नेता: नरेन्द्र मोदी

डॉ. देबेंद्र प्रधान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 'एक्स' पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, "डॉ. देबेंद्र प्रधान जी ने एक मेहनती और विनम्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने ओडिशा में भाजपा को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए। सांसद और मंत्री के रूप में उनका योगदान गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सशक्तीकरण पर जोर देने के लिए भी उल्लेखनीय है। उनके निधन से दुःखी हूं। मैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने गया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।"

सामाजिक सेवा में उनका योगदान अविस्मरणीय है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने डॉ. प्रधान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के पूज्य पिताजी व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वं डॉ. देवेंद्र प्रधान जी के पार्थिव शरीर को आज नई दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के साथ ही जनसेवा के क्षेत्र में किया गया उनका योगदान अविस्मरणीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहन संवेदनाएं प्रकट करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करें। ■

कदम सिंह नहीं रहे

केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के पिता श्री कदम सिंह का 15 मार्च, 2025 को निधन हो गया। अनुशासन से परिपूर्ण जीवन जीने वाले 92 वर्षीय श्री कदम सिंह ने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली।

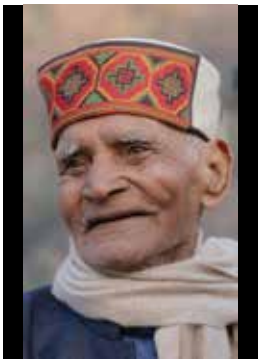

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, कई मुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री कदम सिंह का अंतिम संस्कार उसी दिन शाम को हरियाणा में उनके पैतृक गांव जमालपुर में किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कदम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्री भूपेन्द्र यादव को पत्र लिखा और कहा, "पिता का चले जाना जीवन के सबसे दुःखद क्षणों में से एक है। मैं जीवन के ऐसे कठिन क्षणों में आपके दर्द को समझ सकता हूं। उनके निधन से आपके जीवन में जो शून्यता आई है, उसे शब्दों में बयां करना कठिन है।" श्री मोदी ने आगे कहा, "श्री कदम सिंह के मूल्य आपके व्यक्तित्व और व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी।" ■

प्रधानमंत्री ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ ज्ञानवर्धक बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में प्रसिद्ध पॉडकास्टर और एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रिडमैन के साथ आकर्षक और विचारोत्तेजक बातचीत की। तीन घंटे तक चली इस चर्चा में प्रधानमंत्री श्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए उनके प्रारंभिक वर्षों और सार्वजनिक जीवन में उनकी यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया। प्रसिद्ध एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ यह बहुप्रतीक्षित तीन घंटे का पॉडकास्ट 16 मार्च, 2025 को रिलीज़ हुआ।

लेक्स फ्रिडमैन ने इस बातचीत को अपने जीवन की 'सबसे शक्तिशाली बातचीत' में से एक बताया।

पॉडकास्ट के बारे में लेक्स फ्रिडमैन की 'एक्स' पर पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, "@lexfridman के साथ यह वास्तव में आकर्षक बातचीत थी, जिसमें मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई। अवश्य जुड़ें और इस संवाद का हिस्सा बनें!" ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

रामचन्द्र राय

श्री रामचंद्र राय भारतीय जनसंघ के जिला संयोजक रहे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने प्रयागराज में डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी से शिक्षा प्राप्त की तथा बचपन से ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े रहे। वह संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे तथा उन्होंने भारतीय किसान संघ में प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

श्री राय गोपालगंज जिला के संघचालक रहे। वह सेवा भारती से भी जुड़े रहे। वर्ष 1980 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर मीरगंज विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा। उन्होंने ओडिशा एवं असम में संघ के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री राय आपातकाल के दौरान मीसा के तहत 18 महीने तक मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद रहे। वह सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे।

श्री राय अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक संगठन एवं संघ के प्रति समर्पित रहे। ■

प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा को संबोधित किया

महाकुंभ ने एकता की भावना को मजबूत किया: नरेन्द्र मोदी

आज के युवा अपनी परंपराओं, आस्था और विश्वासों को गर्व के साथ अपना रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ उनके मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मार्च को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने देश के उन असंख्य नागरिकों को हार्दिक बधाई दी जिनके प्रयासों से महाकुंभ की भव्य सफलता सुनिश्चित हुई। महाकुंभ को सफल बनाने में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के सामूहिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सरकार, समाज और इसमें शामिल सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों को स्वीकार किया और उनकी सराहना की। श्री मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों और प्रयागराज के नागरिकों का उनके अमूल्य समर्थन और भागीदारी के लिए विशेष उल्लेख करते हुए आभार व्यक्त किया।

महाकुंभ ने दुनिया को भारत की भव्यता दिखाई

श्री मोदी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए लोगों के अथक प्रयासों को रेखांकित किया और इसकी तुलना गंगा को धरती पर लाने के पौराणिक भागीरथ से किया। उन्होंने लाल किले से अपने संबोधन के दौरान 'सबका प्रयास' के महत्व पर भी जोर देने का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ ने दुनिया को भारत की भव्यता दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा, "महाकुंभ लोगों के अटूट विश्वास से प्रेरित सामूहिक संकल्प, भक्ति और समर्पण की अभिव्यक्ति है।"

श्री मोदी ने महाकुंभ के दौरान देखी गई राष्ट्रीय चेतना की गहन जागृति पर टिप्पणी की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यह चेतना राष्ट्र को नए संकल्पों की ओर प्रेरित करती है और उसे उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ ने राष्ट्र की क्षमताओं के बारे में कुछ लोगों की शंकाओं और आशंकाओं को निर्मूल कर दिया।

राष्ट्र की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डालते हुए, पिछले वर्ष अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और इस वर्ष महाकुंभ के बीच समानता दर्शाते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये आयोजन अगली सहस्राब्दी के लिए राष्ट्र की तत्परता को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना इसकी अपार क्षमता को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि मानव इतिहास की तरह ही राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण के रूप में काम करते हैं।

प्रयागराज महाकुंभ: राष्ट्र की जागृत भावना का प्रतीक

श्री मोदी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान आध्यात्मिक पुनरुत्थान, शिकागो में स्वामी विवेकानंद के जोरदार भाषण और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्षणों जैसे 1857 के विद्रोह, भगत सिंह की शहादत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 'दिल्ली चलो' आह्वान और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का हवाला देते हुए भारत के ऐतिहासिक मील के पत्थरों पर विचार किया, जिन्होंने राष्ट्र को जागृत किया और नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, "प्रयागराज महाकुंभ भी इसी तरह का एक मील का पत्थर है, जो राष्ट्र की जागृत भावना का प्रतीक है।"

भारत में लगभग डेढ़ महीने तक चले महाकुंभ के दौरान देखे गए जीवंत उत्साह को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं ने सुविधा या असुविधा की बिना चिंता किए अटूट आस्था के साथ भाग लिया और देश की अपार शक्ति का प्रदर्शन किया।

मॉरीशस की अपनी हालिया यात्रा का हवाला देते हुए, जहां

भारत में लगभग डेढ़ महीने तक चले महाकुंभ के दौरान देखे गए जीवंत उत्साह को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं ने सुविधा या असुविधा की बिना चिंता किए अटूट आस्था के साथ भाग लिया और देश की अपार शक्ति का प्रदर्शन किया

वे महाकुंभ के दौरान एकत्र किए गए त्रिवेणी, प्रयागराज से पवित्र जल लेकर गए थे, प्रधानमंत्री ने मॉरीशस के गंगा तालाब में पवित्र जल अर्पित करने के समय भक्ति और उत्सव के गहन माहौल का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों को अपनाने, मनाने और संरक्षित करने की बढ़ती भावना को दर्शाता है।

श्री मोदी ने पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की निर्बाध निरंतरता पर टिप्पणी की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत के आधुनिक युवा महाकुंभ और अन्य त्योहारों में गहरी श्रद्धा के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के युवा अपनी परंपराओं, आस्था और विश्वासों को गर्व के साथ अपना रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ उनके मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है।

विरासत पर गर्व

श्री मोदी ने कहा, "जब कोई समाज अपनी विरासत पर गर्व करता है, तो वह भव्य और प्रेरक क्षण बनाता है जैसाकि महाकुंभ के दौरान देखा गया।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का गर्व एकता को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परंपराओं, आस्था और विरासत से जुड़ाव समकालीन भारत के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, जो देश की सामूहिक ताकत और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि महाकुंभ ने कई अमूल्य परिणाम दिए हैं, जिसमें एकता की भावना सबसे पवित्र भेंट है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे देश के हर क्षेत्र और कोने से लोग प्रयागराज में एक साथ आए, व्यक्तिगत अहंकार को अलग रखते हुए और 'मैं' की बजाय 'हम' की सामूहिक भावना को अपनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न राज्यों के लोग पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बन गए, जिससे राष्ट्रवाद और एकता की भावना मजबूत हुई। श्री मोदी ने कहा कि जब विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग संगम पर 'हर-हर गंगे' का नारा लगाते हैं, तो यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सार को दर्शाता है और एकता की भावना को बढ़ाता है।

जब कोई समाज अपनी विरासत पर गर्व करता है, तो वह भव्य और प्रेरक क्षण बनाता है जैसाकि महाकुंभ के दौरान देखा गया।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का गर्व एकता को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास को मजबूत करता है

श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ ने छोटे और बड़े के बीच भेदभाव की अनुपस्थिति को प्रदर्शित किया, जो भारत की अपार शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के भीतर अंतर्निहित एकता इतनी गहन है कि यह सभी विभाजनकारी प्रयासों को मात देती है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एकता भारतीयों के लिए एक महान सौभाग्य है और विखंडन का सामना कर रहे विश्व में एक महत्वपूर्ण ताकत है।

'विविधता में एकता' भारत की पहचान

श्री मोदी ने दोहराया कि 'विविधता में एकता' भारत की पहचान है, एक भावना जिसे लगातार महसूस किया जाता है और अनुभव किया जाता है, जैसाकि प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता से स्पष्ट होता है। उन्होंने राष्ट्र से विविधता में एकता की इस अनूठी विशेषता को समृद्ध करना जारी रखने का आग्रह किया।

महाकुंभ से मिली अनेक प्रेरणाओं के बारे में बोलते हुए श्री मोदी ने देश में नदियों के विशाल नेटवर्क पर प्रकाश डाला, जिनमें से कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उन्होंने महाकुंभ से प्रेरित होकर नदी उत्सवों की परंपरा का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही कहा कि ऐसी पहलों से वर्तमान पीढ़ी को पानी के महत्व को समझने, नदी की स्वच्छता को बढ़ावा देने और नदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में विश्वास व्यक्त किया कि महाकुंभ से प्राप्त प्रेरणाएं राष्ट्र के संकल्पों को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेंगी। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की सराहना की तथा देशभर के सभी श्रद्धालुओं को नमन किया और सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं।

मुख्य बातें

- मैं उन नागरिकों को नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन संभव हुआ
- महाकुंभ की सफलता में कई लोगों का योगदान है, मैं सरकार और समाज के सभी कर्मयोगियों को बधाई देता हूं
- हमने महाकुंभ के आयोजन में एक 'महा प्रयास' देखा
- इस महाकुंभ का नेतृत्व लोगों ने किया, यह उनके संकल्प से प्रेरित और उनकी अटूट भक्ति से प्रेरित था
- प्रयागराज महाकुंभ एक मील का पत्थर है जो एक जागृत राष्ट्र की भावना को दर्शाता है
- महाकुंभ में सभी मतभेद मिट गए; यह भारत की बहुत बड़ी ताकत है, यह दिखाता है कि एकता की भावना हमारे भीतर गहराई से पैठी है
- आस्था और विरासत से जुड़ने की भावना आज के भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है ■

देश 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जायेगा: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में गृह मंत्रालय ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और एक मज़बूत विधायी खाका खड़ाकर हमारे सुरक्षाकर्मियों के हौसले में वृद्धि करने का प्रयास किया है

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस देश की सुरक्षा, विकास और सार्वभौमिकता को – जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर-पूर्व के उग्रवाद – की तीन बड़ी समस्याओं से हमेशा चुनौती मिलती रही। उन्होंने कहा कि ये तीन नासूर लगभग 4 दशकों से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे और देश के विकास की गति को अवरुद्ध करते रहे।

श्री शाह ने कहा कि इन तीन समस्याओं के कारण 4 दशकों में देश के लगभग 92 हज़ार नागरिक मारे गए। उन्होंने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इन नासूरों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए कोई सुनियोजित प्रयास नहीं हुआ था। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्ति की ओर है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीर में पड़ोसी देश से आए दिन आतंकी घुसते थे, बम धमाके और हत्याएं करते थे और इन घटनाओं के प्रति तत्कालीन केन्द्र सरकारों का रवैया लचीला होता था। वे चुप्पी साध जाते थे, उन्हें बोलने में डर लगता था और साथ ही वोट बैंक का डर भी था। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। मोदी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं कि देश में बम धमाका कर सके। हमारी सरकार आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, लेकिन हमने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया।

श्री शाह ने कहा कि कश्मीर में अलगाववाद का मूल कारण धारा 370 थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण धारा 370 कई वर्षों तक चलती रही। गृह मंत्री ने कहा कि इसी संसद में 5 अगस्त, 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया।

हमारी सरकार के समय आतंकी जहां मारे गए वहीं दफना दिए जाते हैं

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिनसे आतंकियों के साथ भारतीय बच्चों के जुड़ने की संख्या करीब-करीब शून्य हो गई है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले आतंकियों का महिमामंडन होता था और बड़े जुलूस निकलते थे, लेकिन हमारी सरकार के समय में एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मारे गए वहीं दफना दिए जाते हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच 7217 आतंकी घटनाएं हुईं, जो 2014-2024 के बीच घटकर 2242 रह गई। इसी अवधि में कुल मृत्यु में 70 प्रतिशत की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 81 प्रतिशत और सुरक्षाबलों की मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी आई है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अब तक हजारों लोग वामपंथी उग्रवाद की बलि चढ़ चुके हैं। पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर में कई जिलों, तहसीलों और थानों पर कब्जा कर लिया गया था और पूरी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। पैरलेल करेंसी और स्टेम्प पेपर चलाए जा रहे थे। सरकारें बनाई गईं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि वह सदन को जिम्मेदारी के साथ बताना चाहते हैं कि 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, लेकिन पिछले दस साल में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक 1851 सुरक्षाकर्मी मारे गए, लेकिन पिछले दस साल में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या घटकर 509 रही, जो 73 प्रतिशत की कमी है। नागरिकों की मृत्यु का आंकड़ा

4766 से घटकर 1495 रह गया है, जो 70 प्रतिशत की कमी है। श्री शाह ने कहा कि दिसंबर, 2023 में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, जिसके बाद एक ही साल के भीतर 380 नक्सली मारे गए। 1194 नक्सली गिरफ्तार हुए और 1045 ने सरेन्डर किया।

पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्या को भी हम समाप्त करने की कगार पर हैं। वहां भी हिंसक घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है। हताहत सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 72 प्रतिशत और हताहत नागरिकों की संख्या में 85 प्रतिशत की कमी आई है। हमारी सरकार आने का बाद सभी हथियारबंद समूहों से बात की। वर्ष 2019 से लेकर अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। श्री शाह ने कहा कि कुल मिलाकर 10,900 युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में आए हैं। बोडोलैंड में हजारों युवा विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की यह नीति है कि जो ड्रग लेता है, वह इस बुराई का पीड़ित है और ड्रग का व्यापार करने वाला गुनहगार।

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 25 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त की गई, जबकि 2014 से 2024 के दौरान ये बढ़कर एक करोड़ किलोग्राम से ज्यादा हो गई। 2004 से 2014 के दौरान 40 हज़ार करोड़ रुपये की ड्रग पकड़ी गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच 1 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग पकड़ी गई है।

देश की हर भाषा भारत की संस्कृति का गहना है

श्री अमित शाह ने कहा कि देश की हर भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने स्थानीय भाषाओं के लिए काम किया है और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में शुरू किया है। श्री शाह ने कहा कि भाषा के नाम पर देश को बांटने को छोड़ अब विकास की बात होनी चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद तक अंग्रेज़ों की संसद द्वारा, उनके शासन को मज़बूत और सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए आपराधिक कानून चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई, 2024 से तीन नए आपराधिक कानूनों– भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पूरे देश में लागू किया गया। श्री शाह ने कहा कि अगले 3 साल में ये नए कानून हर राज्य के हर पुलिस स्टेशन में शत-प्रतिशत लागू हो जाएंगे, जिसके बाद देश में किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय प्राप्त हो सकेगा।

> पूर्वोत्तर की समस्या को भी हम समाप्त करने की कगार पर हैं। वहां भी हिंसक घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है। हताहत सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 72 प्रतिशत और हताहत नागरिकों की संख्या में 85 प्रतिशत की कमी आई है

आपदा प्रबंधन

श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले आपदा प्रबंधन 'राहत केंद्रित' था और इसे रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ बनाया गया था, जबकि 2014 के बाद 'बचाव केंद्रित' दृष्टिकोण अपनाया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 में SDRF की निधि 37,727 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2014 के बाद यह बढ़कर एक लाख 20 हजार 780 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 2004 से 2014 तक NDRF की निधि 27,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2014 के बाद यह बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि किस पैमाने पर देश को आपदा से बचाने का काम हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि पद्म पुरस्कारों में ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले है जो सामान्य लोगों के हीरो थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के अंदर छोटे-छोटे परिवर्तन लाने में खपा दिया। ऐसे लोगों को आज किसी सिफारिश की जरुरत नहीं हैं।

मुख्य बातें

- मोदी सरकार में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्ति की ओर
- मोदी सरकार न आतंकवाद को सहेगी न आतंकवादियों को
- कुछ लोग अपने घोटाले और भष्टाचार को छिपाने के लिए भाषा की आड़ ले रहे हैं
- मोदी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं कि देश में बम धमाका कर सके
- अगले 3 साल में पूरे देश में पूर्णतः लागू हो जायेंगे नये आपराधिक कानून
- अगले 6 माह में एक पूर्ण स्वदेशी ड्रोनरोधी मॉड्यूल देश के सामने होगा
- NIA ने 95% दोषसिद्धि दर हासिल की है, जो दुनियाभर की एंटी टेरर एजेंसी में सबसे अधिक है
- मोदी सरकार ने PFI को बैन कर उसके सदस्यों को चुन-चुन कर जेल भेजा और देश को सामने आने वाले एक बड़े खतरे को समाप्त किया
- ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले और उस पैसे को आतंकवादी गतिविधियों में लगाने वालों को मोदी सरकार कभी नहीं छोड़ेगी
- कुछ लोग पंजाब में भिंडरावाला बनना चाहते थे, हमने उन्हें असम में जेल में डालने का काम किया ■

तपेदिक से लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर

जगत प्रकाश नड्डा

आज विश्व तपेदिक (टीबी) दिवस है। इस अवसर पर मैं बहुत गर्व के साथ बता सकता हूं कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भारत किस तरह से अपनी सफल रणनीति का नया अध्याय लिख रहा है। हाल ही में संपन्न '100-दिवसीय सघन टीबी-मुक्त भारत अभियान' ने न केवल नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी दिखाया कि समुदायों को संगठित करने का कार्यक्रम इस बीमारी से प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने में कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह अभियान 7 दिसंबर, 2024 को टीबी के मामलों का पता लगाने में तेजी लाने, मृत्यु-दर को कम करने और नए मामलों को रोकने के उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था।

इस अभियान ने टीबी का जल्द पता लगाने के लिए अत्याधुनिक रणनीति अपनाई, जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि बिना लक्षण वाले मरीजों की भी पहचान हो सके और फिर उनका फौरन इलाज शुरू किया गया। अन्यथा उनका उपचार ही नहीं हो पाता। पोर्टेबल एक्स-रेमशीनों को उच्च जोखिम वाले लोगों के पास ले जाया गया, जिनमें मधुमेह, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, एचआईवी संक्रमित, बुजुर्ग और टीबी के रोगियों के घरेलू संपर्क में रहने वाले लोग शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से संचालित एक्स-रे ने संदिग्ध टीबी मामलों को तुरंत चिह्नित किया, फिर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट (नात) का उपयोग करके मामलों की पुष्टि की गई और उनका जल्दी से इलाज किया गया, जिससे संक्रमण पर लगाम लगी और लोगों की जान बचाई गई।

यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंचा, जिसके तहत टीबी हो सकने के जोखिम वाले 2.97 करोड़ लोगों की जांच की गई। इस गहन प्रयास के कारण 7.19 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई। इनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे और इस अभिनव दृष्टिकोण के बिना वे छूट जाते। इस कदम से टीबी संक्रमण की श्रृंखला टूट गई। यह सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि इस रोग के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है।

भारत से टीबी उन्मूलन अब जन-भागीदारी द्वारा संचालित एक जन-आंदोलन है। पूरे भारत में 13.46 लाख से ज्यादा निक्षय शिविर आयोजित किए गए, जिनका सांसदों, विधायकों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों सहित 30,000 से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। कॉरपोरेट जगत व नागरिकों की भागीदारी से यह विचार मजबूत हुआ है कि टीबी उन्मूलन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामूहिक मिशन है।

इस मिशन में जन-भागीदारी के अनूठे उदाहरण देखने को मिले। 22 संबंधित मंत्रालयों में टीबी जागरूकता, पोषण किट वितरण, टीबी मुक्त भारत के लिए शपथ लेने जैसी 35,000 से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की गईं। इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यापार संघों, व्यावसायिक संघों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ 21,000 से अधिक गतिविधियां की गईं और 78,000 शैक्षणिक संस्थानों में 7.7 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने टीबी जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियों में भाग लिया। विभिन्न जेलों, खदानों, चाय बागानों, निर्माण स्थलों और कार्य स्थलों पर 4.17 लाख से अधिक संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग की गई। अभियान अवधि के दौरान त्योहारों पर 21,000 से अधिक टीबी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें धर्मगुरुओं और विभिन्न समुदायों के प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण ने इस भागीदारी की आधारशिला रखी है। न केवल पोषण, बल्कि मनो-सामाजिक व व्यावसायिक समर्थन के लिए रोगियों को गोद लेने के वास्ते व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाया गया। टीबी रोगियों के लिए सहायता अब अस्पतालों तक सीमित नहीं है, यह घरों, गांवों और कार्यस्थलों पर भी हो रही है। निक्षय मित्र पहल के माध्यम से व्यक्ति और संगठन टीबी पीड़ित परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस पहल में हजारों पोषण किट पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। सिर्फ 100 दिनों में 1,05,181 नए निक्षय मित्रों को पंजीकृत किया गया। पोषण और टीबी से उबरने के बीच महत्वपूर्ण संबंध को देखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी टीबी रोगी इस लड़ाई को अकेले न लड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी

यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंचा, जिसके तहत टीबी हो सकने के जोखिम वाले 2.97 करोड़ लोगों की जांच की गई। इस गहन प्रयास के कारण 7.19 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई। इनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे और इस अभिनव दृष्टिकोण के बिना वे छूट जाते

टीबी रोगियों के लिए विभेदित टीबी देखभाल कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत उपचार प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, यह निर्देशित किया गया है कि यदि किसी टीबी रोगी का वजन कम पाया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उसके लिए अनुकूलित पोषण और उपचार योजना तैयार करेंगे और हर महीने उसकी प्रगति की निगरानी करेंगे।

इस अभियान की गति ने यह भी दर्शाया है कि समाज और सरकार का समग्र दृष्टिकोण कैसा परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। टीबी के प्रति जागरूकता और सेवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए 22 मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। देश भर के स्कूलों में टीबी जागरूकता संदेशों को सुबह की सभाओं में शामिल किया गया। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने तो हजारों आगंतुकों को मुफ्त टीबी जांच की पेशकश करने के लिए अपने क्लस्टर कार्यालयों के नेटवर्क का लाभउठाया। इन विविध प्रयासों ने टीबी से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ दिया और सही सूचनाओं के साथ टीबी उन्मूलन को सार्वजनिक चेतना के केंद्र में ला दिया।

यह 100 दिवसीय अभियान तो अभी शुरुआत है। भारत इन प्रयासों को पूरे देश में बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरेक नागरिक की- चाहे वह कहीं पर भी रहता हो, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण इलाज और अटूट सामुदायिक समर्थन तक पहुंच बन सके। जिस तरह भारत ने कोविड-19 की जांच को तेजी से आगे बढ़ाया, उसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय टीबी उन्मूलन के अगले चरण में निवेश कर रहा है, ताकि अंतिम छोर तक तेज और सटीक जांच हो सके।

चाहे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हो या हमारे पोलियो उन्मूलन अभियान की, भारत ने पहले भी समुदाय संचालित कार्रवाई की शक्ति देखी है, अब टीबी मुक्त भारत अभियान आम लोगों के नेतृत्व वाला एक और आंदोलन बन रहा है। दरअसल, जब नवाचारों की पहुंच बनती है और सरकारें, समुदाय व व्यक्ति एकजुट होते हैं, तब असंभव भी वास्तविकता बन जाता है। भारत टीबी से सिर्फ लड़ नहीं रहा है, हम इसे हरा भी रहे हैं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री है)

इस अभियान की गति ने यह भी दर्शाया है कि समाज और सरकार का समग्र दृष्टिकोण कैसा परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। टीबी के प्रति जागरूकता और सेवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए 22 मंत्रालयों ने मिलकर काम किया

मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना की

सरकार 2026-27 तक एक करोड़ घरों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ इस योजना के सुचारू व समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों में प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है तथा सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देकर इस योजना के माध्यम से सरकार को बिजली की लागत में अनुमानित रूप से सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है

'**पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई)**', जोकि घरेलू छतों पर स्थापित की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सौर पहल है, ने 10 मार्च, 2025 तक कुल 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह परिवर्तनकारी योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को तेजी से नया आकार दे रही है। कुल 47.3 लाख आवेदनों की प्राप्ति के साथ इस पहल ने पहले ही 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है, जिससे सौर ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं अधिक सुलभ हो गई है।

कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की गिरवी-मुक्त ऋण सहित इस योजना के वित्तपोषण के आसान विकल्पों ने इसे अपनाने में और तेजी लाई है। अब तक 3.10 लाख ऋण संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.58 लाख स्वीकृत किए गए हैं और 1.28 लाख वितरित किए गए हैं। इससे सभी के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है।

मात्र 15 दिन की सहज सब्सिडी हस्तांतरण प्रक्रिया और कई लाभार्थियों के लिए शून्य बिजली बिल के साथ यह योजना न केवल घरों को बिजली प्रदान कर रही है, बल्कि लोगों को सशक्त भी बना रही है। पीएमएसजीएमबीवाई के तहत प्रत्येक सौर ऊर्जा संयंत्र 100 पेड़ लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जिससे भारत एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर होता है।

कई राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति

इस योजना ने कई राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उल्लेखनीय रूप से चंडीगढ़ और दमन एवं दीव ने अपने सरकारी भवनों की छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया है और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के मामले में देश में सबसे आगे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से संबंधित समग्र आंकड़ों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार 2026-27 तक एक करोड़ घरों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ इस योजना के सुचारू व समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों में प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है।

मुख्य लाभ

'**प्रधानमंत्री सूर्य घर:** मुफ्त बिजली योजना' में भाग लेने वाले घरों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जाते हैं:

घरों के लिए मुफ्त बिजली: यह योजना छतों पर सब्सिडी वाले सौर पैनल स्थापित करके घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में काफी कमी आती है।

सरकार के लिए बिजली की लागत में कमी: सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देकर इस योजना के माध्यम से सरकार को बिजली की लागत में अनुमानित रूप से सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग: यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत में अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की दिशा में योगदान मिलता है।

कार्बन उत्सर्जन में कमी: इस योजना के तहत सौर ऊर्जा को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

सब्सिडी संबंधी विवरण

इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी घरों की औसत मासिक बिजली खपत और तद्नुरूप छत पर स्थापित उपयुक्त सौर संयंत्र क्षमता के आधार पर भिन्न होती है:

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट)	उपयुक्त छत सौर संयंत्र क्षमता	सब्सिडी सहायता
0-150	1-2 किलोवाट	30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक
150-300	2-3 किलोवाट	60,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक
> 300	3 किलोवाट से अधिक	78,000 रुपये

सब्सिडी के लिए आवेदन और विक्रेता का चयनः इच्छुक घर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां वे छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल उचित प्रणाली के आकार, लाभ संगणक, विक्रेता रेटिंग और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करके निर्णय लेने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल पर सभी सूचनाएं सही ढंग से दर्ज किए जाने के साथ उपभोक्ता द्वारा किए गए छूट संबंधी अनुरोध के बाद सीएफए संबंधी कार्रवाई को पूरा करने में लगने वाला औसत समय लगभग 15 दिन है।

गिरवी-मुक्त ऋणः घरों को 3 किलोवाट तक की आवासीय छत सौर (आरटीएस) प्रणाली की स्थापना के लिए लगभग 7 प्रतिशत के ब्याज पर गिरवी–मुक्त कम ब्याज वाली ऋण सुलभ होगी।

प्रभाव

'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' से आम घरों और पूरे देश के पक्ष में दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद हैः

घरेलू बचत और आय का सृजनः घरों को अपने बिजली बिलों के मामले में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें अपने छत पर स्थापित सौर प्रणाली द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए 3-किलोवाट वाली प्रणाली प्रति माह औसतन 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न कर सकती है, जोकि ऊर्जा और संभावित राजस्व का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है।

सौर क्षमता का विस्तारः इस योजना से आवासीय क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के माध्यम से 30 गीगावाट की सौर क्षमता जुड़ने का अनुमान है, जोकि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

पर्यावरणीय लाभः छत पर स्थापित इन सौर प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवनकाल में यह अनुमान लगाया गया है कि यह योजना 1000 बीयू बिजली उत्पन्न करेगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी लाएगी, जिससे पर्यावरण पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

रोजगार का सृजनः इस योजना से मैन्यूफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) और अन्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे देश में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप 'पीएम सूर्य घरः मुफ़्त बिजली योजना' भारत में उत्पादित सौर मॉड्यूल और सेल के उपयोग को अनिवार्य करके घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग का समर्थन करती है। 10 मार्च, 2025 तक इस योजना ने छत पर 3 गीगावाट से अधिक की सौर क्षमता की स्थापना की सुविधा प्रदान की है और इसमें मार्च, 2027 तक अतिरिक्त 27 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल इनवर्टर के स्थानीय उत्पादन और बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) संबंधी घटकों को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी तथा मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा मिलेगा।

आदर्श सौर ग्राम

इस योजना के 'आदर्श सौर ग्राम' घटक के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। इस घटक के लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित आदर्श सौर ग्राम को एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

उम्मीदवार गांव के रूप में अर्हता हासिल करने के लिए उस गांव को 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000) से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। गांवों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा पहचाने जाने के छह महीने बाद उनकी समग्र वितरित अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले गांव को एक करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। डीएलसी की देखरेख में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, जिससे इन आदर्श गांवों का सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा में परिवर्तित होना और उनके द्वारा देश भर के अन्य गांवों के लिए एक मानक स्थापित करना सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

'पीएम सूर्य घरः मुफ़्त बिजली योजना' नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत की यात्रा में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में शामिल है, जो लाखों परिवारों के लिए सौर ऊर्जा को सुलभ, किफ़ायती और प्रभावशाली बनाती है। अब जबकि 10 लाख सौर संयंत्रों की स्थापना का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, यह योजना सौर ऊर्जा से संचालित एक करोड़ घरों के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। पर्याप्त सब्सिडी, वित्तपोषण संबंधी आसान विकल्प और एक सुव्यवस्थित डिजिटल आवेदन प्रक्रिया की पेशकश करके यह कार्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण भारत के आम घरों द्वारा न्यूनतम वित्तीय बोझ के साथ स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना सुनिश्चित करता है। बिजली की लागत कम करने के अलावा यह योजना ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव की राह में भारत का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। ■

नव वर्ष–नव संकल्प

शिवप्रकाश

भारतीय कालगणना के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विक्रमी संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। आंग्ल तिथि के अनुसार 30 मार्च रविवार का यह दिन है। भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक अनेक ऐतिहासिक प्रसंग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ जुड़े हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी संवत, सृष्टि प्रारंभ दिवस के कारण सृष्टि संवत, श्रीराम जी का राज्याभिषेक, कलयुग संवत, युधिष्ठिर संवत, विक्रम संवत (2082), शालिवाहन शक संवत (1947), युगाब्द (5127), मालव संवत, गुडी पाडवा, आर्य समाज स्थापना, उगादि, गुरु अंगद देव का जन्म दिवस एवं झूलेलाल जी का अवतरण दिवस आदि सभी प्रेरणा दिवस इस शुभ दिन के साथ जुड़े हैं। शक्ति की उपासना के प्रतीक नवदुर्गा का प्रारंभ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म भी वर्षप्रतिपदा ही है।

भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक जीवन की समस्त विधाओं में भारत की अग्रगणीयता, आर्थिक समृद्धि, प्रकृति में वसंत अर्थात् सम्यक परिवर्तन की दिशा का संदेश संपूर्ण मानवता को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा देती आई है। भारतीय समाज में वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन में उत्थान के लिए नव वर्ष पर नव संकल्प लेने की परंपरा है। इस विक्रम संवत के आगमन पर हम हर्ष एवं उल्लास के साथ नव वर्ष का स्वागत करें एवं भावी समाज को संरक्षित करने की दिशा में नवसंकल्प लें।

शारीरिक : 'शरीरमाध्यम् खलु धर्म साधनम्' (अर्थात् धर्म के साधन का मार्ग स्वस्थ शरीर ही है) भारत में असावधानी के कारण हमारा खानपान स्थूल (मोटापा) शरीर का निर्माण कर रहा है। जिसके कारण अनेक रोग हमारे शरीर को अपना घर बना रहे हैं। दुनिया के देशों की तुलना में हमारे देश में गंभीर रोगों का औसत अधिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए "फिट इंडिया" का संदेश दिया था। नव वर्ष पर यदि हम अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में संतुलित आहार, व्यायाम एवं योग को स्थान देंगे तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। हमारा स्वास्थ्य ही राष्ट्र के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसको हम प्रतिदिन का संकल्प बनाएं।

> **नव वर्ष पर यदि हम अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में संतुलित आहार, व्यायाम एवं योग को स्थान देंगे तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। हमारा स्वास्थ्य ही राष्ट्र के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसको हम प्रतिदिन का संकल्प बनाएं**

पारिवारिक : भारतीय समाज के चिरंजीवी होने के अनेक कारणों में से महत्वपूर्ण है हमारी पारिवारिक व्यवस्था। संपूर्ण विश्व इस पारिवारिक व्यवस्था का अध्ययन एवं अनुपालन करने का प्रयास कर रहा है। परिवार के सभी सदस्यों में सामूहिकता, सुरक्षा, परस्पर प्रेम और आत्मीयता का अंकुरण होता है । परिवार टूटने के कारण ही दुनिया के देश अपने बजट का बड़ा भाग सामाजिक सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। भारत में दुनिया की तुलना में यह न्यून है। हम अपने परिवार के वृद्धों को सम्मान एवं आत्मीयता दें। इसका परिणाम होगा कि नवीन पीढ़ी में भी यह संस्कार आएगा। परिवार के सदस्य सामूहिक भोजन, सामूहिक भजन एवं वर्ष में एक-दो बार विशेष प्रसंगों पर वृहद् परिवार मिलन कर पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का संकल्प लें।

भाषा सीखें : विशाल भूभाग वाले अपने देश में अनेक भाषाओं एवं बोलियों का उपयोग होता है। सभी भाषाओं में एक अन्तर्निहित एकात्मता है। हम अपनी मातृभाषा के साथ-साथ एक और दूसरे प्रदेश की भाषा सीखने का प्रयास करें। जिसके कारण हम उस भाषा के साहित्य में छिपे तत्वज्ञान, महापुरुषों एवं परंपराओं को समझ सकेंगे, एवं राष्ट्र की एकात्मता वृद्धि में सहयोगी बन सकेंगे।

नागरिक अनुशासन : देश के संविधान के प्रति आदर एवं श्रद्धा भाव, देश को सुचारू संचालित करने के लिए बनी व्यवस्थाओं का अनुपालन, देश की सम्पत्तियों का संरक्षण, नियमों का पालन, शुचिता पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार करने से देश में अनुशासन का भाव निर्माण होगा। यह अनुशासन ही किसी भी देश की महानता की गारंटी है। अभावग्रस्त समाज के लोगों को शिक्षा, भोजन, कार्यकुशलता निर्माण कर सेवा के माध्यम से समृद्ध करें। अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहते हुए समाज में सुरक्षितता का वातावरण बनाएं। नए-नए प्रयोगों के द्वारा रोज़गार प्रदान करते हुए भारत को आर्थिक समृद्ध कर, विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति में सहायक होना हमारा संकल्प बने।

संयमित एवं सादगी पूर्ण जीवन शैली: पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित सिद्धांत "खर्च में संयम एवं उत्पादन में वृद्धि हम सभी के लिए मार्गदर्शक है।" आय से अधिक खर्च किसी भी समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। समाज में एक दूसरे को देखकर अधिक खर्च की प्रवृत्ति भी

हमारी संस्कृति त्यागमयी एवं सभी के कल्याण का विचार करने वाली है। इस कारण विश्व शांति की गारंटी भारतीय संस्कृति ही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमको इस सांस्कृतिक गौरव का ही स्मरण कराती है। हम स्वयं एवं आने वाली पीढ़ी में अपने महापुरुषों, अपनी परंपराओं के प्रति यह गौरव के भाव को जागृत करने का संकल्प लें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उत्सव को व्यक्तिगत के साथ-साथ समाज का उत्सव बनाते हुए हम अपने व्यक्तिगत जीवन एवं समाज जीवन में यह संकल्प ले तब नव वर्ष की सार्थकता सिद्ध होगी

बढ़ रही है। शादी-विवाह एवं शुभ प्रसंगों के समय बर्बाद होता भोजन यह राष्ट्र की संपत्ति का ही नुकसान है। यह दृष्टि लेकर व्यक्तिगत जीवन में सादगी एवं संयम पूर्ण व्यवहार से समाज को सम्यक दिशा दें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी अन्न की बर्बादी के संबंध में सम्पूर्ण देश को सचेत किया था।

महिला सशक्तीकरण : अपने प्राचीन धर्म ग्रंथो में मां (स्त्री) का बड़ा श्रेष्ठ स्थान (यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः) था। कालांतर में समाज में अनेक कुप्रथाएं आईं। आज भी समाज में हृदय को विदीर्ण करने वाली अनेक घटनाएं होती रहती हैं। महिला हिंसा एवं दुर्व्यवहार को समाप्त करें। समाज में महिलाओं को समान स्थान, समान अवसर, निर्णयों में समान सहभागिता का वातावरण बनाने में हम सभी सहभागी बनें।

पर्यावरण संरक्षण : महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध वाक्य ""The Earth has enough resources for our need but not for our greed." भोगवादी जीवन शैली एवं प्रकृति के संसाधनों पर कब्जे की मनोवृति के कारण हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है। जिसका परिणाम है प्रदूषण एवं तापमान में वृद्धि। अनेक विद्वानों एवं पर्यावरण केंद्रित संस्थाओं के आकड़े हमें चिंतित करने वाले हैं। मनुष्य का जीवन भविष्य में सुरक्षित रहेगा अथवा नहीं यह सभी की चिंता का विषय है। हम इस नव वर्ष पर अपना जीवन पर्यावरण को संरक्षित करनेवाला बनाएं, एवं जल, भोजन, वायु, वनस्पति सभी शुद्ध रहे, इसका संकल्प लें।

संस्कृति स्वाभिमान : हमारी संस्कृति त्यागमयी एवं सभी के कल्याण का विचार करने वाली है। इस कारण विश्व शांति की गारंटी भारतीय संस्कृति ही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमको इस सांस्कृतिक गौरव का ही स्मरण कराती है। हम स्वयं एवं आने वाली पीढ़ी में अपने महापुरुषों, अपनी परंपराओं के प्रति यह गौरव के भाव को जागृत करने का संकल्प लें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उत्सव को व्यक्तिगत के साथ-साथ समाज का उत्सव बनाते हुए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन एवं समाज जीवन में यह संकल्प ले तब नव वर्ष की सार्थकता सिद्ध होगी। ■

{लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं}

अटलजी में एक सच्चा पत्रकार सदैव विद्यमान रहा

डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

अटलजी ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी देश के लोगों को देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ राष्ट्र हित में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय राजनीति में एक विकल्प देने के उद्देश्य से शुरू हुआ एक राजनीतिक आंदोलन का उन्होंने दशकों तक नेतृत्व किया तथा वह भारत के पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्तित्व अटलजी एक सच्चे राजनेता, लोकतंत्रवादी, नेतृत्वकर्ता, आम सहमति निर्माता और सबसे बढ़कर राजनीति में एक भद्र पुरुष थे। एक राजनेता और एक कवि के रूप में उन्हें देश के भीतर एवं सीमाओं से परे समान रूप से प्यार और प्रशंसा मिली। वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और बचपन से ही विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा की झलक देखने को मिलने लगी थी, यह कारण है कि उन्होंने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। जहां एक ओर उनकी वक्तृत्व-कला एवं कविता के लिए उनकी प्रशंसा की गई, वहीं उनकी बौद्धिक क्षमताओं, लेखन कौशल और विभिन्न मुद्दों की समझ को बहुत कम उम्र में ही पहचान मिली, यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय महत्व के कार्य सौंपे गए। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक अमिट छाप छोड़ी और सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और उन्हें अपने शुरुआती दिनों में राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और दैनिक स्वदेश के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो 'राष्ट्रधर्म' नाम से एक मासिक पत्रिका शुरू करने की योजना बना रहे थे, ने अटलजी को लखनऊ जाने के लिए कहा, जहां से पत्रिका का प्रकाशन होना था। श्री राजीव लोचन अग्निहोत्री के साथ अटलजी को 'राष्ट्रधर्म' पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे तुरंत सफलता मिली। 'राष्ट्रधर्म' के प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही थी, वहीं वामपंथी बौद्धिक वर्ग के बीच इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से बेचैनी थी। अटलजी के लेखन ने उन्हें बौद्धिक बिरादरी के बीच एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया और 'राष्ट्रधर्म' एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अग्रणी प्रकाशन बन गया। इस बीच 'पांचजन्य' का प्रकाशन शुरू हुआ और अटलजी को इसके संपादन की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसके पहले अंक की ही हर ओर व्यापक प्रशंसा हुई।

लेकिन जल्द ही 1948 में प्रशासन ने 'राष्ट्रधर्म' के कार्यालय को सील कर दिया और कर्मचारियों को जेल में डाल दिया। अटलजी किसी तरह बच निकले और कुछ समय तक इलाहाबाद में रहे। इसी बीच, न्यायालय ने 'राष्ट्रधर्म' के पक्ष में आदेश दिया और उसे पुनः प्रकाशन की अनुमति दे दी गई। अटलजी ने उसी कार्यालय से 'दैनिक स्वदेश' का प्रकाशन शुरू किया, लेकिन कार्यालय को फिर से सील कर दिया गया। इसके बाद अटलजी काशी चले गए और वहां से 'चेतना' नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1950 में उन्होंने फिर से 'दैनिक स्वदेश' के संपादक का दायित्व संभाला। लेकिन सरकार से कोई सहायता न मिलने के कारण एवं वित्तीय कठिनाइयों के चलते प्रकाशन अधिक समय तक नहीं चल सका। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी विज्ञापन मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अटलजी को भारी मन से 'दैनिक स्वदेश' का प्रकाशन बंद करना पड़ा और उन्होंने अंतिम संपादकीय 'अलविदा' में अपनी पीड़ा व्यक्त की। इसके बाद वह लखनऊ से दिल्ली चले गए और 'वीर अर्जुन' का संपादन किया। उनके नेतृत्व में 'वीर अर्जुन' ने भी ख्याति अर्जित करना शुरू कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, तो अटलजी को इस नवगठित राजनीतिक दल की नींव मजबूत करने के लिए भेजा गया। फिर, बाकी सब इतिहास है।

> **अटलजी प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते थे और इसमें दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका हमेशा से मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने से लोकतंत्र मजबूत होगा। वह कहते थे, "प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की एक मूल्यवान संपत्ति है"**

अटलजी प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते थे और इसमें दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका हमेशा से मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने से लोकतंत्र मजबूत होगा। वह कहते थे, "प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की एक मूल्यवान संपत्ति है।" वह समाज में संपादकों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत महत्व देते थे और कहते थे, "संपादक को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और स्वयं के प्रति सच्चा होना चाहिए। किसी को आत्मा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक है कि पहले आत्मा को जीवित रखा जाए।" उनका मानना था कि सरकार एवं मीडिया के बीच एक स्वस्थ संबंध होना चाहिए और वह किसी भी प्रेस सेंसरशिप के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि "सरकार को सेंसरशिप की व्यवस्था को लागू करने जैसे कठोर कदम उठाने से पहले प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए।" उन्हें भारतीय मीडिया की कर्तव्य भावना पर बहुत भरोसा था, वह कहते थे, "कुछ अपवादों को छोड़कर; भारतीय प्रेस ने पत्रकारिता के उच्च मानदंड को बनाए रखा है।"

उन्हें आने वाली पीढ़ी के पत्रकारों से भी उम्मीदें थीं और उनकी प्रतिभा एवं पेशे के प्रति प्रतिबद्धता पर भरोसा था। उन्होंने कहा, "आज

के पत्रकार अधिक जानकार, अधिक मेहनती, अधिक खोजी और अधिक आक्रामक हैं।" 12 जुलाई, 1998 को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के 11वें द्विवार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में मीडिया को और अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया से प्रतिस्पर्धा कर सके। ऐसा करने के लिए उन्होंने मीडिया में गुणवत्ता, मानक और दक्षता बनाए रखने पर जोर देना होगा और समाचारों का चयन इस तरह करना होगा कि वह समाज एवं राष्ट्र के हित में हो। पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "समाज का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, बुराइयों को उजागर किया जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर प्रेस का रवैया ऐसा होना चाहिए कि देश के लोगों के मन में देश के बारे में सही तस्वीर बने और बाहरी लोग भी हमारे बारे में सच्चाई से आकलन कर सकें।"

अटलजी राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन पत्रकारिता के दिनों को उन्होंने हमेशा संजोकर रखा। उन्होंने एक बार कहा था, "मैं एक अच्छा पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन राजनीति की कठिन जमीन में उलझ गया। राजनीति ने मेरे कवि मन का गला घोंट दिया है। अब मैं एक वाचाल बन गया हूं।"

अटलजी पत्रकारिता के पेशे के सामने आने वाली समस्याओं से भी अवगत थे। उन्होंने कहा, "पत्रकारिता कभी मिशन थी, फिर पेशा बनी और अब व्यवसाय बनती जा रही है।" 12 जुलाई 1998 को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के 11वें द्विवार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अपना सार्वजनिक जीवन भी अखबार से ही शुरू किया था। तब अखबार में काम करना एक मिशन था। देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई चल रही थी और हर कोई उस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता था। आज पत्रकारिता का चेहरा बदल गया है। यह एक व्यवसाय बन गया है। व्यवसायी होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, छपने वाली चीजें दिल और दिमाग पर असर करने वाली होनी चाहिए।" 27 अगस्त, 1999 को लखनऊ में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका पायनियर के विमोचन के अवसर पर उन्होंने पत्रकारिता की जिम्मेदारियों एवं समाज में विचारों को लेकर उसके कर्तव्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जिन अखबारों के पास संसाधनों की कमी है, उन्हें विचारों के आधार पर आगे बढ़ना होगा। अखबारों को झूठ उजागर करने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन यह काम सही तरीके से होना चाहिए। यह सही है कि अखबार भी एक उद्योग है, लेकिन यह साबुन और तेल बेचने जैसा उद्योग नहीं है। पत्रकारिता की अपनी मान्यताएं और उद्देश्य हैं। इसकी जिम्मेदारी कहीं अधिक है। अगर पत्रकारिता उच्च उद्देश्य पर आधारित नहीं होगी, तो मुश्किलें आएंगी। मैं खुद पत्रकार रहा हूं, इसलिए अखबारों को जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उससे मैं भलीभांति अवगत हूं। अब पत्रकारिता में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और अखबारों की प्रतिस्पर्धा टीवी चैनलों से है, जो हर आधे घंटे पर समाचार देते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि इसके बावजूद न तो अखबारों की लोकप्रियता कम हुई है और न ही उनकी उपयोगिता पर कोई प्रतिकूल असर पड़ा है। किसी भी अखबार के लिए समाचार के साथ-साथ विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर जिनके पास संसाधन कम हैं, उन्हें विचारों की ताकत के आधार पर आगे बढ़ना होगा।"

अटलजी ने भारतीय राजनीति में एक अनूठी और गौरवशाली विरासत छोड़ी है। वास्तव में वह भारत की उस भावना के प्रतिनिधि थे, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं ने राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार दिया है। वह राजनीतिक दल और शासन में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में विश्वास करते थे, लेकिन राजनीति में आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्तियों का वह हमेशा विरोध करते थे। उनका राष्ट्रवाद लोकतांत्रिक भावना से ओत-प्रोत था, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सरोकारों के विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने की परंपरा के माध्यम से भारतीय समाज की विविधताओं को संबोधित किया जाता था। अपने लंबे संसदीय जीवन में वह विपक्ष में रहते हुए भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे। राष्ट्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं पर उनकी पकड़ के कारण ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकाचार और मूल्य प्रणाली के दायरे में समाधान खोजने का प्रयास किया। वह एक ऐसे नेता थे, जो जमीन से जुड़े थे और अपनी राजनीतिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे, जिससे पता चलता था कि उनमें एक सच्चा पत्रकार सदैव विद्यमान रहा।

अटलजी ने भारतीय राजनीति में एक अनूठी और गौरवशाली विरासत छोड़ी है। वास्तव में वह भारत की उस भावना के प्रतिनिधि थे, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं ने राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार दिया है। वह राजनीतिक दल और शासन में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में विश्वास करते थे, लेकिन राजनीति में आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्तियों का वह हमेशा विरोध करते थे

वह लंबे समय तक राजनीति जीवन में रहे, जहां उन्हें लोगों का प्यार, स्नेह और सम्मान मिला। वह एक उत्कृष्ट वक्ता थे और अपनी करिश्माई अपील से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। देश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था और देश की जनता के बढ़ते समर्थन से यह सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हर मोर्चे पर देश का नेतृत्व किया और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। भारत एक शांतिपूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उभरा, जिसने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी खुद पर भरोसा बनाए रखा। एक सच्चे 'अटल' की तरह वह कभी दबाव में नहीं झुके, न ही एक संपादक के रूप में और न ही एक राजनेता के रूप में। उन्होंने सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखी, साथ ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया और भारत को विभिन्न मोर्चों पर 'आत्मनिर्भर' बनाया। जैसाकि अटलजी ने अपने एक भाषण में कहा था, उन्होंने काल के कपाल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग उभरते हुए नए भारत के लिए मार्गदर्शक बन गया है। ■

भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध व क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत हुए

प्रधानमंत्री श्री मोदी की मॉरीशस की राजकीय यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11-12 मार्च को मॉरीशस की दो दिवसीय सफल राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम, जीसीएसके, एफआरसीपी के साथ मॉरीशस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। 11 मार्च को हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मॉरीशस और भारत के बीच उस विशेष और अद्वितीय संबंध पुष्टि की जो इतिहास, भाषा, संस्कृति, विरासत, पारस्परिक संबंधों और मूल्यों के साझा बंधनों को देखते हुए अनुपम है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोगों के बीच आपसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित मॉरीशस-भारत संबंध पिछले कई दशकों में मजबूती से बढ़कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं।

इस दौरान, भारत के प्रधानमंत्री ने मार्च, 2015 में मॉरीशस की अपनी पिछली यात्रा को याद किया। उस दौरान भारत के 'सागर दृष्टिकोण' यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को उजागर किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 'सागर दृष्टिकोण' को साकार करने के लिए मॉरीशस एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मॉरीशस सरकार के व्यापक समर्थन की सराहना की।

राजनीतिक आदान-प्रदान

दोनों नेताओं ने माना कि उनके द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर उच्च स्तर का विश्वास और आपसी समझ है, जिसे जारी रखने में दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और यात्राओं की अहम भूमिका है। यह भी उल्लेख किया गया कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत अतिथि देश के रूप में मॉरीशस की भागीदारी ने सभी क्षेत्रों में मेलजोल और गहरी चर्चा को बढ़ावा दिया। दोनों नेताओं ने इन चर्चाओं को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

विकास साझेदारी

दोनों नेताओं ने उल्लेख किया कि भारत स्वतंत्रता के बाद से मॉरीशस के विकास के लिए अग्रणी भागीदार रहा है और इसके बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने भारत-मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सर्वोच्च न्यायालय के नये भवन, नया ईएनटी अस्पताल, 956 सामाजिक आवास इकाइयां और शैक्षणिक टैबलेट जैसी कई उच्च प्रोफ़ाइल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में भारत के सहयोग पर प्रकाश डालते हुए भारत से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया, जो मॉरीशस के विभिन्न क्षेत्रों के परिदृश्य का हिस्सा हैं और जिनसे पिछले कुछ वर्षों में मॉरीशस के सभी वर्गों को लाभ हुआ है।

यह देखते हुए कि भारत से सहायता प्राप्त जन-केंद्रित विकास सहायता से मॉरीशस के मैत्रीपूर्ण लोगों को ठोस लाभ होता है और ये परियोजनाएं मॉरीशस के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देती हैं, दोनों नेताओं ने निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की:

- 100 इलेक्ट्रिक बसों और उनसे संबंधित चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करने की दिशा में काम करना
- दोनों पक्षों के बीच भारतीय रुपये में प्रथम मूल्यवर्गित ऋण समझौते के अंतर्गत मॉरीशस में 100 किलोमीटर की जल पाइपलाइन को बदलने का काम आरंभ करना
- मॉरीशस सरकार की ओर से चिह्नित स्थल पर नए संसद भवन के संबंध में चर्चा को अंतिम रूप देना और भारत की अनुदान सहायता से इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए रूपरेखा तय करना
- गंगा तालाब स्पिरिचुअल सैंक्चुअरी के पुनर्विकास पर चर्चा को अंतिम रूप देना और भारत की अनुदान सहायता से इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए रूपरेखा तय करना

मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण

यह देखते हुए कि भारत ने हमेशा मॉरीशस में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा मानव संसाधन विकास संबंधी आवश्यकताओं के प्रति अपनी रचनात्मक भूमिका निभायी है, दोनों नेताओं ने निम्न प्रमुख बिंदुओं पर प्रतिबद्धता व्यक्त की:

- भारत सरकार के तकनीकी और आर्थिक सहयोग के ढांचे और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत चल रही क्षमता निर्माण पहलों को जारी रखना
- भारत में पांच वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के माध्यम से मॉरीशस के 500 सिविल सेवकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करना
- एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संस्थागत रूप देकर मॉरीशस के राजनयिकों के लिए मौजूदा प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाना और मजबूत करना

प्रधानमंत्री ने मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रहण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री धर्मबीर गोखूल ने 12 मार्च को प्रधानमंत्री श्री मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द् ऑर्डर ऑफ द् स्टार एंड की ऑफ द् इंडियन ओशन (जीसीएसके) से सम्मानित किया। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय राजनेता को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस पुरस्कार को भारत और मॉरीशस के बीच विशेष मैत्री तथा भारत के 1.4 अरब लोगों और मॉरीशस में रहने वाले उनके 1.3 मिलियन भाइयों-बहनों को समर्पित किया।

राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर भारतीय नौसेना का एक पोत भी मॉरीशस बंदरगाह पहुंचा। ■

अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्र में आपसी सहयोग से दोनों देशों को काफी लाभ हुआ है और यह भारत की ओर से मॉरीशस के साथ अपने विशेष संबंधों को दिए गए महत्व को दर्शाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने के लिए दोनों नेता निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमत हुए:

- भारत-मॉरीशस उपग्रह के सफल विकास और प्रक्षेपण की दिशा में मिलकर काम
- मॉरीशस में विभिन्न अस्थायी पैमानों पर मौसम और जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली, समुद्री तरंगों के मापन और उनके संबंध में जानकारी दर्ज करने के लिए वेव राइडर बॉयज़ और विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए आपातकालीन प्रणाली लागू करने में सहयोग

स्वास्थ्य और शिक्षा सहयोग

- दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के समर्थन का उल्लेख करते हुए मॉरीशस के लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लाभ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- दोनों नेताओं ने स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के विकास में विशेषज्ञता साझा करने पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) और मॉरीशस के उच्च शिक्षा मंत्रालय के बीच चल रही बातचीत का भी स्वागत किया।

आर्थिक और व्यापार संबंधी सहयोग

दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर निर्णय और अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक और व्यापार संबंधों में प्रमुख मील का पत्थर हैं। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों में विविधता लाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की:

- दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए सीईसीपीए के तहत उच्च शक्तियों वाली संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र आयोजित करना
- स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपये और मॉरीशस के रुपये में व्यापार निपटान की सुविधा प्रदान करना, जो साझेदार केंद्रीय बैंकों द्वारा स्थानीय मुद्रा निपटान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में द्विपक्षीय व्यापार के जोखिम को कम करने की दिशा में काम करेगा

रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग

दोनों नेताओं ने कहा कि रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और संरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए मॉरीशस और भारत की साझा प्रतिबद्धता है, दोनों देश इस क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार हैं और उन्होंने समुद्री चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र में बड़े रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करने का अपना संकल्प दोहराया।

सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंध

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक बंधन और लोगों के बीच पारस्परिक संबंध मॉरीशस-भारत के विशिष्ट संबंधों का आधार हैं। इस सिलसिले में दोनों नेता निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमत हुए:

- भारत के गिरमिटिया मजदूरों के प्रलेखित अभिलेखों को संरक्षित करने में महात्मा गांधी संस्थान को सहयोग प्रदान करना, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण और संस्थागत सहायता प्रदान करना शामिल है
- चार धाम और रामायण ट्रेल के साथ-साथ भारत में प्राचीन धार्मिक मंदिरों और स्थानों की यात्रा के माध्यम से पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना ■

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 6 समझौते और हुईं 4 घोषणाएं

दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत शुरू

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री के तौर पर श्री लक्सन की भारत की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी 17 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया, जिसमें श्री लक्सन मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन भाषण दिया। प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने राजघाट पर महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की साझा इच्छा दोहराई, जो दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। उन्होंने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि-तकनीक, अंतरिक्ष, लोगों के आवागमन और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निकट सहयोग पर सहमति व्यक्त की।

क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर बातचीत

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर बातचीत की और बहुपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय अधिनियम, विशेषकर 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री अधिनियम सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप नौवहन और उड्डयन की स्वतंत्रता तथा समुद्र के अन्य वैध उपयोग के अधिकार की पुष्टि की।

व्यापार, निवेश और वित्तीय मामलों में सहयोग

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच निरंतर व्यापार और निवेश का स्वागत किया और द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने दोनों देशों के व्यावसायियों को आपसी संबंध विकसित करने तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पूरक क्षेत्रों में सहयोग के लिए उभरते आर्थिक और निवेश अवसरों का पता लगाने को प्रोत्साहित किया।

राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने संसदीय सम्पर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की परस्पर नियमित यात्रा पर सहमति व्यक्त की। भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य स्टाफ कॉलेज आदान-प्रदान, नौसेना के जहाजों द्वारा एक-दूसरे के बंदरगाहों पर नियमित ठहराव और उच्च-स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान सहित रक्षा सम्पर्क में निरंतर प्रगति का स्वागत किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आपदा प्रबंधन में सहयोग

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अनुसंधान, वैज्ञानिक संबंधों, प्रौद्योगिकी साझेदारी और नवोन्मेष के महत्व को रेखांकित करते हुए परस्पर हित में ऐसे अवसरों की तलाश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत के नेतृत्व का स्वागत किया और न्यूजीलैंड के 2024 से इसके सदस्य के तौर पर मजबूत समर्थन दोहराया।

प्रमुख घोषणाएं

1. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई
2. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने वाली व्यवस्था पर बातचीत की शुरुआत हुई
3. न्यूजीलैंड हिंद-प्रशांत ओशंस पहल में शामिल हुआ
4. न्यूजीलैंड आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन का सदस्य बना

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 6 समझौते

- भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड तथा न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर - पारस्परिक मान्यता समझौता
- भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन
- भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी पर आशय पत्र
- भारत के शिक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्रालय के बीच शिक्षा सहयोग समझौता
- भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा न्यूजीलैंड के खेल मंत्रालय के बीच खेलों में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन ■

भारत में सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे।"
— भारत का संविधान

भारत मूर्त विरासत के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जहां प्रागैतिहासिक काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक के स्मारक, स्थल और पुरावशेष मिलते हैं। हांलाकि एएसआई, राज्य पुरातत्व विभाग और इनटैक जैसे विभिन्न संगठनों ने इस विरासत के कुछ हिस्सों का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन बहुत कुछ बिखरा हुआ या अलिखित है। एकीकृत डेटाबेस के न होने से अनुसंधान, संरक्षण और प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी मुद्दे पर निर्मित विरासत, स्थलों और पुरावशेषों का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए स्मारक और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमए) शुरू किया गया था। मानकीकृत दस्तावेज़ीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जन जागरूकता के माध्यम से एनएमएमए का मकसद भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है।

स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमए)

वर्ष 2007 में स्थापित एनएमएमए भारत की निर्मित विरासत और पुरावशेषों के डिजिटलीकरण और दस्तावेज़ीकरण के लिए ज़िम्मेदार है। इसने स्मारकों और पुरावशेषों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर संकलित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

एनएमएमए की प्रमुख उपलब्धियां

पुरातन वस्तुओं का डिजिटलीकरण: 12,34,937 पुरावशेषों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें एएसआई संग्रहालयों/मंडलों/शाखाओं से 4,46,068 और अन्य संस्थानों से 7,88,869 पुरावशेष शामिल हैं।

निर्मित विरासत और स्थल: 11,406 स्थलों और स्मारकों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

एनएमएमए के प्रमुख उद्देश्य

- बेहतर प्रबंधन और अनुसंधान के लिए निर्मित विरासत, स्मारकों और पुरावशेषों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उसका दस्तावेज़ीकरण करना।
- केंद्रीय, राज्य, निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पुरावशेषों का एक समान दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करना।
- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- राज्य विभागों, स्थानीय निकायों, संग्रहालयों, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।

डिजिटलीकरण के मूख्य दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस बनाने के लिए एनएमएमए ने समान दस्तावेज़ीकरण के लिए मानक तय किए हैं:

- निर्मित विरासत/स्थलों (द्वितीयक स्रोतों से) की तस्वीरें अनकंप्रेस्ड टिफ प्रारूप (300 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन) में होनी चाहिए।
- पुरावशेषों की तस्वीरें अनकंप्रेस्ड टिफ प्रारूप (300 डीपीआई) में ली जानी चाहिए। यदि तस्वीरें एनईएफ/आरएडब्ल्यू प्रारूप में ली गई हैं, तो उन्हें बिना किसी बदलाव के टिफ में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- लघु चित्रों की तस्वीरें या तो टिफ (300 डीपीआई) में उपयुक्त पृष्ठभूमि के साथ ली जा सकती हैं या स्कैन की जा सकती हैं।

डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत (आईएचडीएस) अनुसंधान

आईएचडीएस पहल का मकसद केवल दस्तावेज़ीकरण की सीमाओं से आगे जाकर भारत की विरासत को संरक्षित करने और साझा करने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना है। आईएचडीएस का प्रमुख उद्देश्य निम्न है:

- भारतीय सांस्कृतिक संपत्तियों पर जोर देते हुए डिजिटल विरासत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- अंतर्विषयी अनुसंधान में मदद करने के लिए मल्टीमीडिया विरासत संसाधनों के लिए भंडारण, संरक्षण और वितरण तंत्र की स्थापना करना।

विरासत संरक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका

3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर विज़न और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल उपकरणों ने विरासत संरक्षण के स्वरूप को बदल दिया है। ये प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित की अनुमति देती हैं:

- पांडुलिपियों, स्मारकों और कलाकृतियों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण।
- खत्म हो चुकीं या क्षतिग्रस्त विरासत संरचनाओं का वर्चुअल पुनर्निर्माण।
- शिक्षा और पर्यटन के लिए इंटरैक्टिव अनुभव।

निष्कर्ष

भारत की सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण और दस्तावेज़ीकरण, इसके संरक्षण और पहुंच के लिए बेहद ज़रूरी है। स्मारक और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमए) अभिलेखों को मानकीकृत करके, हितधारकों को प्रशिक्षित करके और जन जागरूकता को बढ़ावा देकर इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रौद्योगिकी और सहयोग की मदद से एनएमएमए यह सुनिश्चित करता है कि भारत की विशाल विरासत का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण और संरक्षण हो सके और इसे अनुसंधान और शिक्षा के लिए उपलब्ध कराया जा सके। एक एकीकृत और व्यापक डेटाबेस न केवल इनके संरक्षण में सहायता करेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगा। ■

प्रधानमंत्री ने क्रू-9 अंतरिक्ष यात्रियों को दी बधाई

सुनीता विलियम्स और क्रू-9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता के वास्तविक मायने क्या हैं: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मार्च को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित क्रू-9 अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी ने क्रू-9 अंतरिक्ष यात्रियों के साहस, दृढ़ संकल्प और अंतरिक्ष अन्वेषण में उनके योगदान की सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण से अभिप्राय मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखना और उन सपनों को यर्थाथ में परिवर्तित करने का साहस दिखाना है। सुनीता विलियम्स ने एक पथप्रदर्शक और आदर्श के रूप में अपने पूरे करियर में इस भावना का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है।

एक्स पर अपने एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, "क्रू-9 आपका स्वागत है, पृथ्वीवासियों ने आपकी प्रतीक्षा की। यह उनकी दृढ़ता, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू-9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता के वास्तविक मायने क्या हैं। विशाल अज्ञात के सामने उनका अडिग दृढ़ संकल्प सदैव लाखों लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।

अंतरिक्ष अन्वेषण का अर्थ मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखना और उन सपनों को यर्थाथ में परिवर्तित करना है। सुनीता विलियम्स ने एक पथ प्रदर्शक और एक आदर्श के रूप में अपने पूरे करियर में इस भावना का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है।

हमें उन सभी लोगों पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता और लगन तथा तकनीक और दृढ़ता का सामंजस्य होता है तो कार्य सिद्ध होते हैं।" ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

पोर्ट लुइस (मॉरीशस) में 11 मार्च, 2025 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मॉरीशस में 11 मार्च, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत करता भारतीय समुदाय

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 17 मार्च, 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 17 मार्च, 2025 को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दर्शन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन

नई दिल्ली में 17 मार्च, 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक सुश्री तुलसी गबार्ड से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 18 मार्च, 2025 को ट्यूरिन (इटली) में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले दल से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 03 अप्रैल, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह